सूर्योदय - 06:26
सूर्यास्त - 05 : 44

अधिकतम तापमान 32.0°
न्यूनतम तापमान 19.0°

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

ओपन सर्च

RNI No.DELHIN/2015/66886

खबरें और विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें

Mob. : 9210092542
opensearchnews@gmail.com

E-mail | opensearchdelhi@gmail.com
Facebook | https://www.facebook.com/opensearch.co.in
Website | www.opensearch.co.in

वर्ष : 12 अंक : 354 नई दिल्ली, शनिवार 28 नवम्बर-2026
नई दिल्ली, हरियाणा, बिहार से प्रकाशित
` मूल्य : 02 रूपए | पृष्ठ : 08

परिसीमन संशोधन विधेयक को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई बैठक में इन विधेयकों को मंजूरी दी गई

नई दिल्ली.एजेंसी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने परिसीमन संशोधन विधेयक और इससे संबंधित महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सेवा तीर्थ में हुई बैठक में इन विधेयकों को मंजूरी दी गई। यह माना जा रहा है कि सरकार इन विधेयकों को 30 नवम्बर से बुलाई गई संसद की बैठक में पेश करने वाली है।

परिसीमन विधेयक में सभी राज्यों में अनुपात के आधार पर लोकसभा में सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढाने का प्रस्ताव है। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा में सीटों की यह संख्या अगले 25 वर्षों तक फ्रीज रहेगी। परिसीमन विधेयक के आधार पर ही लोकसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि बैठक में सरकार सदन की स्वीकृति के लिए अति महत्वपूर्ण कामकाज लायेगी।

उन्होंने कहा कि 30 नवंबर और एक दिसंबर को लोकसभा में बहुत ही महत्वपूर्ण 'बिजनेस' लाया जायेगा और उसे ही दो और तीन दिसंबर को राज्यसभा में पेश किया जायेगा। उन्होंने इस संबंध में किसी विधेयक का नाम नहीं लिया और कहा कि कामकाज क्या होगा इसकी जानकारी उचित समय पर दे दी जायेगी। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय ने संसद की इस बैठक को मानसून सत्र का दूसरा भाग बताया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और 13 अगस्त को दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से सत्रावसान नहीं किया गया था। इस तरह दोनों सदनों की ये बैठकें मानसून सत्र का ही विस्तार होंगी। आमतौर पर मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के कुछ दिन बाद सत्रावसान कर दिया जाता है और नवम्बर के अंतिम सप्ताह में शीतकालीन सत्र बुलाया जाता है।

सत्रावसान करने के बाद नए सत्र के लिए राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है लेकिन इस बार मानूसन सत्र का सत्रावसान न किए जाने की वजह से राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है। विपक्ष मानसून सत्र का सत्रावसान न किए जाने को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाता रहा है और इसे संसदीय परंपराओं का उल्लंघन करार देता रहा है। विपक्षी दलों विशेष रूप से कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का संसदीय लोकतंत्र में भरोसा नहीं है।

विपक्ष लगातार यह भी कहता रहा है कि सरकार परिसीमन विधेयक तथा महिला आरक्षण संबंधी विधेयक को जोड़ तोड़ से पारित कराने के लिए अचानक संसद की बैठक बुलाना चाहती है इसीलिए मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं किया जा रहा है। सरकार गत अप्रैल में परिसीमन विधेयक लोकसभा में लाई थी लेकिन विपक्ष की एकजुटता के कारण मतविभाजन में यह विधेयक गिर गया था।

संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण इसे पारित कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत है। इस बीच सरकार इन विधेयकों को पारित कराने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से परोक्ष रूप से बातचीत करती रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा कई अन्य मंत्री लगातार यह कहते रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार महिला आरक्षण विधेयक पारित अवश्य कराएगी।



परिसीमन विधेयक के आधार पर ही लोकसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि बैठक में सरकार सदन की स्वीकृति के लिए अति महत्वपूर्ण कामकाज लायेगी

परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र से पहले परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव है। परिसीमन विधेयक को लेकर राजनीतिक दलों के बीच समर्थन और विरोध की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है, जबकि डीएमके और बीआरएस ने कुछ शर्तों के साथ समर्थन देने के संकेत दिए हैं। वहीं, कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को संविधान पर हमला करार दिया है। इससे पहले अप्रैल में सरकार ने परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयकों को पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं जुटा सकी थी। इस कारण विधेयक पारित नहीं हो पाए थे। पिछले सात महीनों में बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच सरकार इस बार पूरी तैयारी के साथ विधेयक को संसद में लाने की रणनीति बना रही है।

भारत की राष्ट्रपति वैद्यरत्नम् आयुर्वेद कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोहों के समापन समारोह में हुई शामिल



त्रिशूर.एजेंसी

भारत की राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मु केरलम के त्रिशूर में वैद्यरत्नम् आयुर्वेद कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोहों के समापन समारोह में शामिल हुईं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि केरलम का योगदान केवल आयुर्वेद की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में तक सीमित नहीं है। इसने आयुर्वेद की शास्त्रीय शिक्षा की समृद्ध एवं जीवंत परंपरा को सहेजने और आगे बढ़ाने का कार्य किया है।

इसने वैद्य परिवारों की पीढ़ियों से चली आ रही चिकित्सा संबंधी ज्ञान-परंपरा को भी समृद्ध किया है। प्रामाणिक आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण की इसकी परंपराएं आज भी निरंतर फल-फूल रही हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुर्वेद की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसका प्रामाणिक साहित्य कभी भी केवल संस्कृत भाषा तक सीमित नहीं रहा है। केरलम में मलयालम और मणिप्रवालम भाषाओं में भी अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना की गई है और टीकाएं लिखी गई हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रत्येक आयुर्वेद महाविद्यालय को प्रामाणिक एवं प्रभावी आयुर्वेद के माध्यम से समाज की सेवा करनी चाहिए। साथ ही, वहां समसामयिक एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आयुर्वेद की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। ऐसे महाविद्यालयों को ऐसे विशेषज्ञ तैयार करने में सक्षम होना चाहिए, जिनमें वर्तमान और भावी पीढ़ियों की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की समझ और दूरदृष्टि हो। उन्होंने यह जानकर प्रसन्नता व्यक्त की कि वैद्यरत्नम् आयुर्वेद कॉलेज की कार्य-संस्कृति इसी आदर्श के अनुरूप है।

• आयुर्वेद महाविद्यालयों को प्रामाणिक एवं प्रभावी आयुर्वेद के माध्यम से समाज की सेवा करनी चाहिए : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु

• आयुर्वेद की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसका प्रामाणिक साहित्य कभी भी केवल संस्कृत भाषा तक सीमित नहीं रहा है

राष्ट्रपति ने कहा कि वैद्यरत्नम् आयुर्वेद कॉलेज जैसे आयुर्वेदिक संस्थान वर्ष 2047 तक स्वस्थ और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रपति ने केरलम की आयुर्वेदिक परंपरा की एक विशिष्ट विशेषता का उल्लेख करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की कि वहां आयुर्वेद की पेशेवर प्रथाओं के साथ परोपकार की भावना भी जुड़ी हुई है।

उच्चतम न्यायालय का तिरुप्परनकुंद्रम मामले में आज दीप जलाने का निर्देश

नई दिल्ली.एजेंसी उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के तिरुप्परनकुंद्रम मामले में शुक्रवार को एक बेहद अहम आदेश पारित करते हुए आज 'दीपथून' (दीप स्तंभ) पर दीप जलाने का निर्देश दिया और मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर लगी रोक हटाते हुए राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पहाड़ी की चोटी पर स्थित सिकंदर दरगाह से कम से कम 50 मीटर की दूरी पर प्रत्येक श्रद्धालु को दीप जलाने की अनुमति होगी। अदालत ने मंदिर और दरगाह दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को तैनात करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने सुब्रमण्यमस्वामी मंदिर के न्यासी बोर्ड को निलंबित कर दिया है और पूर्व न्यायाधीशों न्यायमूर्ति एस. वैद्यनाथन तथा न्यायमूर्ति वी. पार्थिबन को रिसीवर नियुक्त किया है।

स्वस्थ भारत ही विकसित भारत@2047 का आधार है : उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन

उपराष्ट्रपति ने होली फैमिली अस्पताल के नए सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का किया उद्घाटन

नई दिल्ली.ओपन सर्च

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के ओखला स्थित होली फैमिली अस्पताल के नए सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर होली फैमिली अस्पताल स्मारिका 2026 भी जारी किया तथा नए ब्लॉक के निर्माण से जुड़े व्यक्तियों को सम्मानित किया। अस्पताल की ऐतिहासिक विरासत का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इसकी आधारशिला वर्ष 1953 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने रखी थी। उन्होंने कहा कि इस विरासत की निरंतरता इस बात को दर्शाती है कि नेक उद्देश्यों के साथ स्थापित संस्थान किस प्रकार पीढ़ी-दर-पीढ़ी समाज की सेवा करते रहते हैं। जाति, पंथ, धर्म अथवा आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रति



अस्पताल की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए सी. पी. राधाकृष्णन ने कहा कि भारत की सभ्यतागत परम्परा का दर्शन आपसी सम्मान और प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता पर आधारित है।

उन्होंने कहा कि अच्छे कार्यों और निःस्वार्थ सेवा सदैव प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उनकी सराहना की जानी चाहिए। कैंसर से मुकाबला करने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को रेखांकित करते हुए उपराष्ट्रपति ने देशभर के कैंसर उपचार संस्थानों को एक साझा मंच पर लाने का आह्वान किया, ताकि वे अनुसंधान, ज्ञान और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान कर सकें। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सा अनुसंधान और नवाचार के लाभ समस्त मानवता तक पहुंचना चाहिए तथा उन्हें कुछ देशों अथवा सम्पन्न वर्गों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इस प्रकार के सहयोग को मजबूत करने के लिए पहल करने की अपनी तत्परता भी व्यक्त की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नए सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक से विशि?ट स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी सुविधाओं की सफलता अंततः इस बात पर निर्भर करेगी कि वे उन्नत चिकित्सा उपचार के साथ किफायती सेवाओं, करूणा और मानवीय संवेदनशीलता का कितना बेहतर समन्वय कर पाती हैं।

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक
ओपन सर्च
दिल्ली,हरियाणा और बिहार से प्रकाशित

NATIONAL ENGLISH DAILY
OPEN SEARCH
PUBLISHED FROM DELHI, GOA & CHHATTISGARH



66/1, Janpath, Connaught Place, New Delhi-110001
Phone .: 9210092542
E-mail .: opensearchnews@gmail.com
Website : www.opensearch.co.in
www.facebook.com/opensearch.co.in /open_search/ @opensearch2 open search

पंचकूला के प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ेंगी दो इलेक्ट्रिक बसें, मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने नवीनीकृत बस टर्मिनल, सेक्टर-5 का भी किया उद्घाटन

कदम सिंह/ओपन सर्च ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों के एक साथ दर्शन कराने के लिए बेहतर, सुविधाजनक और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में माता मनसा देवी मंदिर परिसर, पंचकूला स्थित संस्कृत गुरुकुल से दो इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

यह बस सेवा श्री माता मनसा देवी मंदिर से शुरू होकर चंडी माता मंदिर और पिंजौर गार्डन होते हुए कालका स्थित श्री काली माता मंदिर तक संचालित होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य परिवहन के सेक्टर-5, पंचकूला स्थित नवीनीकृत बस टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकूला मां शक्ति की उपासना का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।

यहां की वादियों में मां के विभिन्न स्वरूपों का वास है, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर शीश नवाने आते हैं। श्रद्धालुओं, विशेषकर बुजुर्गों और महिलाओं को इन प्रमुख धार्मिक स्थलों के एक साथ दर्शन करने में परिवहन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अलग-अलग स्थानों तक पहुंचने के लिए निजी वाहनों पर निर्भरता और बार-बार परिवहन के साधन बदलने की परेशानी के कारण कई श्रद्धालु सभी मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाते थे। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की इसी सुविधा को ध्यान में रखते हुए आज दो प्रदूषण-मुक्त इलेक्ट्रिक बसों की सेवा शुरू की गई है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य और 'लाइफ-पर्यावरण के लिए जीवनशैली' के मंत्र को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बस सेवा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सुविधाजनक समय-सारणी और डिजिटल व्यवस्था है। दोनों बसें प्रतिदिन छह चक्कर लगाएंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष क्यूआर कोड भी जारी किया गया है, जिसे स्कैन करके श्रद्धालु अपने मोबाइल फोन पर बस की वास्तविक लोकेशन और समय-सारणी की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।



यह बस सेवा श्री माता मनसा देवी मंदिर से शुरू होकर चंडी माता मंदिर और पिंजौर गार्डन होते हुए कालका स्थित श्री काली माता मंदिर तक संचालित होगी

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया 'खेल महाकुम्भ हरियाणा-2026' के शुभंकर का लोकार्पण

हरियाणा के खिलाड़ियों का जोश और उत्साह ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत : मुख्यमंत्री नायब सैनी

ओपन सर्च ब्यूरो



चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शुक्रवार को 'खेल महाकुम्भ हरियाणा-2026' के शुभंकर का लोकार्पण किया। राज्य पशु काला हिरण की थीम पर तैयार किया गया यह शुभंकर हरियाणा की पहचान, सांस्कृतिक विरासत और प्रदेश के खिलाड़ियों की फुर्ती, सतर्कता, संतुलन तथा लक्ष्य के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इस अवसर पर हॉकी के पूर्व कप्तान सरदार सिंह, एशियाई खेलों की पदक विजेता परवीन हुड्डा, नरेंद्र बॉक्सर को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा इजिप्ट में जाने वाले हॉकी जूनियर टीम के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों का जोश और उत्साह ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है।

हमें गर्व है कि जब भी पदकों की तालिका बनती है, उसमें हरियाणा का नाम सबसे ऊंचा होता है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि खेल महाकुम्भ उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने और प्रदेश का नाम रोशन करने का एक बड़ा मंच प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि काला हिरण अपने अद्भुत वेग, फुर्ती, सतर्कता, संतुलन और सौम्यता के लिए जाना जाता है। यही गुण हरियाणा के खिलाड़ियों में भी दिखाई देते हैं। खिलाड़ी जब मैदान में उतरते हैं तो उनमें काला हिरण जैसी फुर्ती, एकाग्रता और लक्ष्य को भेदने की क्षमता नजर आती है। उन्होंने कहा कि शुभंकर के माध्यम से प्रदेश के युवाओं और आमजन को पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता और प्राकृतिक धरोहर को सहेजने का संदेश भी दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल महाकुम्भ की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 30 खेलों में 18 हजार खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, कौशल और खेल भावना का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिताओं का आयोजन दो चरणों में प्रदेश के 11 विभिन्न शहरों में किया जाएगा। उन्होंने खेल विभाग, प्रशासनिक अधिकारियों और आयोजन से जुड़े सभी लोगों को सफल आयोजन के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल महाकुम्भ सरकार की दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में छिपी खेल प्रतिभाओं को उचित अवसर, मार्गदर्शन और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। यही प्रतिभाएं आगे चलकर ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में तिरंगे की शान बढ़ा सकती हैं। वार्षिक खेल कैलेंडर के अनुसार, इस महाकुम्भ की गतिविधियां 16 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं और राज्य स्तरीय मुकाबलों से पहले पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर चयन ट्रायल आयोजित किए गए हैं। इन ट्रायल में युवाओं की बढ़-चढ़कर भागीदारी हरियाणा में विकसित हो रही नई खेल संस्कृति का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि खेल केवल शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक एकाग्रता का माध्यम नहीं हैं, बल्कि युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने के साथ-साथ अनुशासन, टीमवर्क, नेतृत्व क्षमता और हार-जीत को समान भाव से स्वीकार करने की सीख भी देते हैं। खेलों पर किया गया निवेश प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य और स्वस्थ समाज के निर्माण में निवेश है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में हरियाणा में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां देने से लेकर खेल अकादमियों, खेल नर्सरियों, प्रशिक्षण सुविधाओं और आधुनिक खेल ढांचे के विस्तार तक लगातार काम किया गया है। हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी भर्ती नियमों के तहत अब तक 260 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ग्रुप-ए, बी और सी की सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

उन्होंने कहा कि ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों सहित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपये तक के नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। पिछले 12 वर्षों में प्रदेश के 17 हजार 676 खिलाड़ियों को 931 करोड़ रुपये की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को तैयारी के लिए अग्रिम राशि भी दी जाती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों को 1500 रुपये तथा 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों को 2 हजार रुपये मासिक छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है। खेल ग्रेडेशन नीति में संशोधन कर हरियाणा स्टेट गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी खेल ग्रेडेशन का लाभ दिया गया है, जिससे उन्हें सरकारी नौकरियों सहित अन्य अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि खेल रत्न, द्रोणाचार्य, अर्जुन, ध्यानचंद और तेनजिंग नोर्गे अवॉर्ड विजेताओं को अब प्रतिमाह 20 हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है।

वहीं, भीम अवॉर्ड विजेताओं को प्रतिमाह 5 हजार रुपये मानदेय दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी खिलाड़ी की सफलता के पीछे गांव की मिट्टी, स्कूल का मैदान और शुरुआती प्रशिक्षण की अहम भूमिका होती है। इसी उद्देश्य से प्रदेश में 2 हजार खेल नर्सरियां खोली गई हैं, जहां लगभग 40 हजार बच्चे सुबह-शाम अभ्यास कर रहे हैं। इसके अलावा, 25 आवासीय खेल अकादमियां स्थापित की गई हैं, जिनमें खिलाड़ियों को प्रतिदिन 500 रुपये की दर से डाइट मनी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पिछले लगभग 12 वर्षों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 1100 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। खिलाड़ियों को चोट लगने की स्थिति में बेहतर उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पंचकूला स्थित ताऊ देवीलाल खेल परिसर में लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय स्तर का 'ए-स्टार' उन्नत वैज्ञानिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। यह उत्तर भारत में अपनी तरह का पहला और सबसे आधुनिक केंद्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में लगातार शानदार प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है।

एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर चौथा स्थान प्राप्त किया, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने 30 पदकों का योगदान दिया। भारत के 21 स्वर्ण पदकों में से 14 स्वर्ण पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। इसी प्रकार, पैरा एशियाई खेलों में भारत ने 114 पदक जीतकर अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसमें हरियाणा के पैरा खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण सहित कुल 31 पदक हासिल किए।

राष्ट्रमंडल खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश के 39 पदकों में से 11 पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे खेल महाकुम्भ के शुभंकर से हर दिन स्वयं को कल से बेहतर बनाने की प्रेरणा लें। जीत और हार खेल के दो पहलू हैं, लेकिन सच्ची खेल भावना, ईमानदारी और अपना शत-प्रतिशत समर्पण ही एक सच्चे खिलाड़ी की सबसे बड़ी पहचान है।

मुख्यमंत्री ने मुक्केबाज गुंजन को 1 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि से किया सम्मानित



चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर निवास पर हांसी के ढाणा कलां गांव की होनहार मुक्केबाज गुंजन को एक करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया। गुंजन ने सेनेगल के डकार में आयोजित यूथ ओलंपिक 2026 की बॉक्सिंग स्पर्धा के 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया है। इससे पूर्व भी गुंजन ने 2026 अंडर-19 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप (जकार्ता, इंडोनेशिया) और 2026 वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर कप (बैंकॉक, थाईलैंड) में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुंजन की असाधारण प्रतिभा, अनुशासन और संघर्ष की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण अंचल की बेटी ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्वर्णिम सफलता हासिल कर यह सिद्ध कर दिया है कि हरियाणा की बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि गुंजन की यह उपलब्धि प्रदेश के अन्य युवाओं और खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। हरियाणा की खेल नीति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी एवं खिलाड़ी-हितैषी खेल नीति के कारण आज हरियाणा देश में खेलों का पावरहाउस बन चुका है। खिलाड़ियों को जमीनी स्तर से ही आधुनिक सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, नर्सरियां और अंतरराष्ट्रीय स्तर की पदक विजेता राशि समय पर उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि खिलाड़ी बिना किसी चिंता के केवल अपने खेल और उत्कृष्ट प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर सकें। मुख्यमंत्री ने गुंजन और उनके परिवार को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

गुरुग्राम को आज मिलेगी 100 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, सार्वजनिक परिवहन को मिलेगा नया विस्तार

ओपन सर्च ब्यूरो,चंडीगढ़। गुरुग्राम में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुलभ, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में आज महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। जिला की सड़कों पर अब 100 नई इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी, जिससे न केवल यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी, बल्कि पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने और वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के प्रयासों को भी गति मिलेगी। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड के बेड़े में शामिल की गई इन 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी शनिवार, 28 नवंबर को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर गुरुग्राम के सेक्टर 48 ई-बस डिपो का उद्घाटन भी करेंगे। गुरुग्राम के सेक्टर-48 स्थित जीएमसीबीएल बस डिपो में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करेंगे।

केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वहीं, पटौदी की विधायक श्रीमती बिमला चौधरी, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर तथा गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के सीईओ डी.के. बेहेरा ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किया।

राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एसएलईसीए) के लिए आवेदन आमंत्रित

ओपन सर्च ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग तथा हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (हरेडा) द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एसएलईसीए-2026) प्रदान किए जाएंगे। इस संबंध में विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में ऊर्जा दक्षता और सतत ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह पुरस्कार विभिन्न निर्धारित श्रेणियों में दिए जाएंगे, जिनमें अधिकतम 2 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि का प्रावधान है।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस पुरस्कार के लिए एमएसएमई सहित विभिन्न उद्योगों, वाणिज्यिक, सरकारी, संस्थानों तथा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों आदि के भवनों, नवाचार, नई प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं, सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा ऑडिटिंग, ग्रीन बिल्डिंग और ईसीबीसी लागू करने वाली फर्मों या एजेंसियों तथा डिस्कॉम्स के सब-स्टेशनों की श्रेणियों में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदकों को अपने आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक पोर्टल https:// app.haredasle-ca.in पर जमा करवाने होंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन आवेदन करने के साथ-साथ आवेदक को अपने आवेदन की एक प्रति संबंधित जिले के अतिरिक्त उपायुक्त-सह-मुख्य परियोजना अधिकारी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के कार्यालय में भी जमा करवानी होगी।

हरियाणा में एक आईएएस, छह एचसीएस अधिकारियों का तबादला

ओपन सर्च ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से एक आईएएस और छह एचसीएस अधिकारियों के तबादला एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। आईएएस अधिकारी और राज्य परिवहन विभाग के महानिदेशक निखिल गजराज को हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सचिव का कार्यभार दिया गया है। एचसीएस अधिकारियों में नियुक्ति आदेशों की प्रतीक्षा कर रहीं निशु नी नम्रता सिंघल को अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, हरियाणा तथा अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) नियुक्त किया गया है। होडल की उपमंडल अधिकारी (नागरिक) बेलीना को सहकारी चीनी मिल, पलवल के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

हरियाणा रोडवेज, हिसार के महाप्रबंधक राहुल मित्तल को सहकारी चीनी मिल, पानीपत का प्रबंध निदेशक लगाया गया है। संयुक्त परिवहन आयुक्त, हरियाणा सुरेश रवेश को सहकारी चीनी मिल, जींद का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के उप सचिव संजय बिश्नोई को जिला परिवहन अधिकारी-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, फतेहाबाद नियुक्त किया गया है। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, गुरुग्राम के संयुक्त निदेशक रमित यादव को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, गुरुग्राम के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

जनसंवाद और सीएम विंडो की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर करें समाधान : भोपाल सिंह खदरी

ओपन सर्च ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री भोपाल सिंह खदरी ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम के तहत नागरिकों की शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष सुनवाई के लिए आती हैं। ऐसे में सभी विभागों के अधिकारी इन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायत के निस्तारण के बाद प्रार्थी की संतुष्टि के साथ-साथ संबंधित क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति (प्रोमिनेंट पर्सन) से भी समाधान का सत्यापन करवाना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री के ओएसडी भोपाल सिंह खदरी शुक्रवार को चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ जनसंवाद एवं सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा कर रहे थे।

बैठक में उन्होंने उच्चतर शिक्षा विभाग, जिला नगर योजनाकार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, विभिन्न विश्वविद्यालयों, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंचकूला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, शहरी संपदा विभाग, कृषि एवं सिंचाई विभाग तथा हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड सहित विभिन्न विभागों की शिकायतों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। खदरी ने कहा कि जनसंवाद एवं सीएम विंडो की प्रदेशभर से प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा के लिए शुरू किए गए प्रथम चरण के बाद ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायतों के समाधान की स्थिति में भी सुधार हुआ है।

हरियाणा बना खेलों का हब -प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनवा रहे अपनी प्रतिभा का लोहा : गौरव गौतम

ओपन सर्च ब्यूरो

चंडीगढ़। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा खेलों का हब बन चुका है और प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं, आधुनिक प्रशिक्षण और प्रोत्साहन उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

उन्होंने खिलाड़ियों का आह्वान किया कि वे अनुशासन, मेहनत और खेल भावना को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं तथा खेल को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ खेलें। खेल राज्य मंत्री ने यह बात शुक्रवार को जींद के मोतीलाल पब्लिक स्कूल में वार्षिक मेगा गाला 5.0 खेल कूद प्रतियोगिता शुभारंभ पर बोलते हुए कही। तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने मशाल जलाकर किया। उन्होंने खिलाडियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जीवन में शिक्षा के साथ-साथ खेलों का भी बहुत बड़ा महत्व है। खेल न केवल व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना का भी विकास करते हैं। खेलों से जुड़ा युवा नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहता है और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है।

खेल राज्य मंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि आज के युवा खिलाड़ी अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के बल पर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। एक खिलाड़ी की सफलता केवल उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती, बल्कि इससे उसके परिवार, गांव, क्षेत्र और पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ता है।

रोहतक में चार लोगों की हत्या, हरियाणा की कानून व्यवस्था पर जवाब दे भाजपा सरकार : कुमारी सैलजा

ओपन सर्च ब्यूरो



चंडीगढ़। सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की सदस्य एवं उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा ने रोहतक में एक ढाबे पर गोलीबारी में चार लोगों की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया। सांसद ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि इस वारदात ने एक बार फिर हरियाणा की बिगड़ती कानून व्यवस्था को उजागर कर दिया है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में आए दिन हत्या, फिरौती और गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। अपराधियों का दुस्साहस बढ़ रहा है और आम नागरिकों को अपनी जान की चिंता है। सांसद ने सवाल किया कि लगातार सामने आ रही इन वारदातों के बावजूद भाजपा सरकार ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? आखिर सरकार ने हरियाणा को किस हाल में पहुंचा दिया है कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं? सांसद ने कहा कि व्यापारियों और दुकानदारों को फिरौती की धमकियां मिलने पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करे।

सरकार बताए कि ऐसी शिकायतों पर कितने मामलों में कार्रवाई हुई और धमकी मिलने के बाद पीड़ितों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए। सांसद ने कहा कि शिकायत पर त्वरित कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। कुमारी सैलजा ने मांग की कि रोहतक की वारदात की जांच तेजी से पूरी की जाए और हमलावरों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। सांसद ने मृतकों के परिवारों को उचित सहायता देने की भी मांग की। कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश की जनता को सुरक्षा देने में विफल रही है। मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की समीक्षा करें और सार्वजनिक रूप से बताएं कि हत्या, फिरौती और गोलीबारी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

देहरादून में 'संविधान बचाओ मार्च' में शामिल हुईं उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा

संविधान दिवस पर उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा देहरादून में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ 'संविधान बचाओ मार्च' में शामिल हुईं। सांसद ने भाजपा पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर 'वोट चोरी' करने का आरोप लगाया और पूछा कि जब जनता का वोट ही नहीं बचेगा, तो संविधान कैसे बचेगा? सांसद ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में संविधान, लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा का संघर्ष जारी रहेगा। सैलजा ने कहा कि बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर उत्तराखंड की जनता भाजपा सरकार से नाराज है और बदलाव चाहती है।

हरियाणा में सरकारी धनराशि की सुरक्षा के लिए साइबर सिक्योरिटी की होगी व्यापक समीक्षा

ओपन सर्च ब्यूरो



चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सरकारी योजनाओं के तहत वित्तीय लेन-देन से जुड़ी साइबर सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक आकलन करने के निर्देश दिए हैं। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल वित्तीय लेन-देन में संभावित कमजोरियों की पहचान करना और साइबर धोखाधड़ी तथा अनधिकृत लेन-देन से सरकारी धनराशि की सुरक्षा के लिए मजबूत उपाय सुनिश्चित करना है। मुख्य सचिव ने डिजिटल भुगतान ढांचे और क्लाउड व्यवस्था की साइबर सुरक्षा तथा वित्तीय सुरक्षा उपायों की समीक्षा के लिए हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को समन्वित, तकनीक आधारित और एहतियाती दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी वित्तीय लेन-देन को साइबर खतरों से सुरक्षित रखने के लिए सभी संबंधित विभागों को मिलकर प्रभावी कार्रवाई करनी होगी।

रस्तोगी ने सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को ऐसी सभी सरकारी योजनाओं की विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए, जिनके तहत वित्तीय भुगतान किए जाते हैं और जो साइबर खतरों के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के समूहों के लिए चार से पांच सदस्यों वाली बहुविषयक समितियां गठित करने को कहा। इन समितियों में तकनीकी विशेषज्ञों, एनआईसी के प्रतिनिधियों, वित्त अधिकारियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। ये समितियां संबंधित योजनाओं की कार्यप्रणाली की जांच करेंगी और डिजिटल वित्तीय लेन-देन में सुरक्षा संबंधी कमियों की पहचान करेंगी। मुख्य सचिव ने कहा कि इस आकलन में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म, प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और उनके सुरक्षा ऑडिट रिकॉर्ड की भी समीक्षा की जानी चाहिए। समितियां यह भी जांच करेंगी कि सुरक्षा ऑडिट कब और किस प्रकार किए गए हैं तथा मौजूदा सुरक्षा उपाय संभावित साइबर खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं।

घर के समीप बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : आरती सिंह राव

ओपन सर्च ब्यूरो



चंडीगढ़। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को घर के समीप बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) तथा ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स (बीपीएचयू) का सुदृढ़ीकरण करने से आमजन के स्वास्थ्य सुरक्षा कवच को और अधिक मजबूत करेगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि करनाल के पोपरा, उपलाना और जलमाना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा यमुनानगर के चमरोड़ी में उप-स्वास्थ्य केंद्र और प्रताप नगर में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट के निर्माण कार्यों की संशोधित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 170.32 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है ताकि इन परियोजनाओं को और अधिक गति मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को शीघ्र ही इन स्वास्थ्य संस्थानों का लाभ मिल सके।

इस संबंध में आगे जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि संबंधित जिलों के सिविल सर्जनों से ये संशोधित रफ कॉस्ट एस्टिमेट प्राप्त हुए हैं, जिन्हें स्थल की आवश्यकताओं और संशोधित लागत आकलनों के आधार पर संबंधित जिला परिषदों के कार्यकारी अभियंताओं द्वारा तैयार किया गया है।

उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यमुनानगर जिले के एसएचसी चमरोड़ी के निर्माण कार्य के लिए पूर्व में जारी 55.50 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति के मुकाबले संशोधित लागत 88.71 लाख रुपये आंकी गई है, जिसके लिए 33.21 लाख रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति अपेक्षित है। इसी प्रकार यमुनानगर के ही सीएचसी प्रताप नगर स्थित बीपीएचयू के लिए पूर्व में 50.00 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, जिसकी संशोधित लागत 55.85 लाख रुपये होने पर 5.85 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त करनाल जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत पीएचसी पोपरा के निर्माण कार्य के लिए 424.67 लाख रुपये की पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति के मुकाबले संशोधित लागत 467.01 लाख रुपये हो गई है, जिसके लिए 42.34 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है।

दिल्ली में सगाई से लौट रहे युवक पर चाकू से हमला, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस (एनएसपी) थाना क्षेत्र में सड़क पर हुए मामूली विवाद ने एक युवक की जान ले ली। शकूरपुर में किसी की सगाई से लौट रहे 27 वर्षीय योगेश की आई-20 कार सवार युवकों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोपियों ने उसके गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल योगेश को महाराजा अग्रसेन अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, घटना गुरुवार देर रात डेढ़ बजे की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और योगेश को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मौके से सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।



मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। योगेश की बुआ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें अभी तक पूरी घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। उन्होंने कहा, 'हमें सिर्फ इतना पता चला है कि रात को सगाई से लौटते समय यह घटना हुई। योगेश की उम्र 27 साल थी। पुलिस आई थी लेकिन अभी क्या कार्रवाई हो रही है, हमें नहीं पता।' वहीं, योगेश की दादी ने बताया, 'योगेश सगाई से आ रहा था। उसके साथ और भी लोग थे। योगेश कह रहा था कि इधर से जाऊंगा, मैं तो उधर से ही जाता हूं। दूसरा लड़का बोला नहीं, इधर से चलो। रास्ते में ही मारने-पीटने लगे। दोनों को धक्का देकर वो भागकर आ रहा था, फिर पीछे से क्या मारा, क्या नहीं मारा, हमें नहीं पता।' परिजनों ने कहा कि योगेश बच्चों को स्कूल ले जाने और ले आने का काम करता था। उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। उन्होंने कहा, 'हमारे बच्चे किसी से बोलते भी नहीं हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्यों उसके साथ इस तरह की वारदात हुई।' पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इंस्टाग्राम-अमेजन ठगी : मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 1.04 लाख बरामद

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस की साइबर शाखा ने इंस्टाग्राम पर फर्जी शॉपिंग और अमेजन डिलीवरी के नाम पर चल रही ठगी के बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड अशोक कुमार मीणा सहित दो आरोपियों को दिल्ली और जयपुर से गिरफ्तार किया है। एक पीड़ित महिला से ठगे गए 1.04 लाख भी बरामद कर वापस लौटा दिए गए हैं। पुलिस के अनुसार, गिरोह इंस्टाग्राम पर आकर्षक कीमतों पर सामान बेचने वाले फर्जी शॉपिंग पेज चलाता था। ग्राहकों को कम दाम का लालच देकर एडवांस पेमेंट के लिए व्हाट्सएप पर बुलाया जाता था। इसके बाद आरोपी खुद को अमेजन का डिलीवरी एजेंट बताकर फर्जी व्हाट्सएप नंबर और नकली पहचान पत्रों का इस्तेमाल करते थे। वे ऑफर वेरिफिकेशन, प्रोसेसिंग चार्ज और रिफंड एक्टिवेशन जैसे विभिन्न शुल्कों के नाम पर पीड़ितों से बार-बार पैसे ऐंठते थे। ठगी गई रकम को छिपाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया जाता था, इस एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के क्यूआर कोड के जरिए ट्रांसफर किया जाता था। यह मामला मालवीय नगर की महिला की शिकायत से शुरू हुआ, पीड़ित महिला ने इंस्टाग्राम पर 999 रुपये का बैग ऑर्डर किया था और जिसके बाद उससे कुल 1,03,973 रुपए की धोखाधड़ी की गई। 12 जुलाई, 2026 को दर्ज शिकायत के बाद, पुलिस की एक विशेष टीम ने जांच शुरू की। तकनीकी विश्लेषण और संदिग्ध व्हाट्सएप नंबरों की जांच के बाद, पुलिस जयपुर पहुंची और आरोपी अजय मीणा को गिरफ्तार किया। लगातार तकनीकी निगरानी के बाद, गिरोह के मास्टरमाइंड अशोक कुमार मीणा को 23 नवंबर, 2026 को दिल्ली से पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने चार मोबाइल फोन (जिसमें से एक आईफोन 17 प्रो अपराध से अर्जित धन से खरीदा गया था), नितिन कुमार सिंह के नाम पर फर्जी पैन व आधार कार्ड, अमेजन के नकली आईडी कार्ड और सात फर्जी इंस्टाग्राम शॉपिंग पेजों का डिजिटल डेटा बरामद किया है। इसके अतिरिक्त, पुलिस को 57 अन्य संभावित पीड़ितों की सूची भी मिली है, जिनकी पहचान की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है ताकि पूरे भारत में अन्य पीड़ितों की पहचान की जा सके और उनके पैसे वापस दिलाए जा सकें। दोनों गिरफ्तार आरोपी जयपुर के रहने वाले हैं और इनका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने पकड़ा बेल्ट के बक्कल में छिपा चाकू, हांगकांग से आया था यात्री

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के बेल्ट के बक्कल में छिपा हुआ चाकू बरामद किया। सीआईएसएफ कर्मियों की तेज नजर और पेशेवर सतर्कता से यह छिपा हुआ हथियार पकड़ में आया। यात्री हांगकांग से आया था और उसे आगे रायपुर जाना था। सुरक्षा जांच के दौरान एक्स-बीआईएस इमेज की जांच करते समय स्क्रीनर ने एक असामान्य धातु की वस्तु देखी और बैगेज को भौतिक जांच के लिए भेजा। इसी जांच में बेल्ट के बक्कल में छिपा हुआ चाकू बरामद हुआ। निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया के अनुसार प्रतिबंधित सामान को हटा दिया गया। सीआईएसएफ ने कहा कि यह पकड़ उनकी अटूट सतर्कता और पेशेवर क्षमता और चौकसी के जरिए मजबूत विमानन सुरक्षा बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बता दें कि इससे पहले 28 अक्टूबर को बिहार के गयाजी हवाई अड्डे पर तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने नियमित प्री-एम्बार्केशन सुरक्षा जांच (पीईएससी) के दौरान तस्करी का संदिग्ध सोना बरामद किया था। हवाई अड्डे के घरेलू सुरक्षा होल्ड क्षेत्र में इंडिगो की घरेलू उड़ान से कोलकाता जाने वाले एक यात्री ने अपने हैंड बैगेज को प्री-एम्बार्केशन सुरक्षा जांच बिंदु पर स्क्रीनिंग के लिए रखा था। एक्स-रे बैगेज निरीक्षण प्रणाली (एक्स-बीआईएस) के दौरान ड्यूटी पर तैनात सतर्क सीआईएसएफ स्क्रीनर ने बैग के भीतर छिपी एक असामान्य सघन धात्विक वस्तु की छवि देखी और तुरंत उस बैग को गहन भौतिक जांच (फिजिकल चेक) के लिए अलग किया था। बैगेज की विस्तृत जांच करने पर लगभग 110 ग्राम की बिस्कुट के आकार की सुनहरे रंग की एक धात्विक वस्तु बरामद हुई थी, जिसके सोना होने का संदेह था। यात्री इसके संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका था। त्वरित अंतर-एजेंसी समन्वय का प्रदर्शन करते हुए सीआईएसएफ एएसजी गया के क्राइम इंटेलिजेंस विंग ने तत्काल गया एवं पटना स्थित आयकर विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में सूचित किया था। इसके साथ ही, त्वरित कार्रवाई हेतु सीआईएसएफ एएसजी कोलकाता को भी अग्रिम सूचना साझा की गई थी।

दिल्ली पुलिस ने 17 साल के नौशाद की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को पकड़ा

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस ने सुभाष प्लेस इलाके में 17 वर्षीय नाबालिग की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को पकड़ा है। इनमें दो नाबालिग आरोपी हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि शकूरपुर गांव इलाके में एक झगड़े के बाद लड़के को चाकू मार दिया गया था। पुलिस के अनुसार, यह घटना 26 नवंबर को हुई। मृतक की पहचान 17 वर्षीय नौशाद के रूप में हुई। अधिकारियों ने बताया कि नौशाद और आरोपियों के बीच किसी छोटी-सी बात को लेकर बहस हुई थी। बताया जा रहा है कि यह विवाद हिंसक हो गया, जिसके दौरान नौशाद को चाकू मार दिया गया। घायल नौशाद को तुरंत इलाज के लिए भगवान महावीर अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद सुभाष प्लेस थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 103(1), 126(2) और 3(5) के तहत 26 नवंबर को एक एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने तीन आरोपियों को पकड़ा, जिनमें दो नाबालिग और 21 साल का अतीकुर रहमान शामिल है। पुलिस ने बताया कि बाकी आरोपियों को पकड़ने और इस अपराध में शामिल सभी लोगों की अलग-अलग भूमिकाओं का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने मंत्री कपिल मिश्रा के कार्यालय के बाहर हुई हत्या के मामले में वांछित अमन गाजी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। करावल नगर इलाके के रहने वाले अमन गाजी को बुधवार रात करीब 11.30 बजे नानक सर और थर्ड पुश्ता के बीच एक श्मशान घाट के पास स्पेशल स्टाफ ने रोका था। पुलिस के मुताबिक, उसने पुलिस टीम पर गोली चलाई, जो कांस्टेबल मुकेश की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी। इसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे आरोपी के बाएं पैर में चोट लग गई। बाद में उसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया।

दिल्ली सरकार ने 'शीशमहल' को जनता के लिए खोला, प्रवेश वर्मा बोले- कोविड के समय भी नहीं रुका था काम

नई दिल्ली, एजेंसी।
दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व आधिकारिक आवास को आम लोगों के लिए खोल दिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस बंगले को 'शीश महल' कहकर संबोधित करती रही है। सरकार ने आवास के नवीनीकरण, साज-सज्जा और फर्निशिंग पर हुए खर्च को प्रमुखता से सामने रखते हुए इसे सार्वजनिक अवलोकन के लिए उपलब्ध कराया है।

उन्होंने कहा, 'आज शीशमहल खोलने का उद्देश्य जनता को यह दिखाना है कि उनका पैसा कहां खर्च हुआ है। लोगों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि करदाताओं के पैसे का उपयोग कैसे हो रहा है। जिस व्यक्ति ने एक बार दावा किया था कि वह न तो कार लेगा और न ही बंगला और सरकार से एक मामूली दो कमरों का मकान चाहता था, उसका शुरुआती प्रोजेक्ट बजट 8 करोड़ रुपये था, जो अंत में 58 करोड़ रुपये को पार कर गया।'

प्रवेश वर्मा ने कहा, 'शीशमहल पार्ट 2 भी बनने जा रहा था, जिसे हमारी सरकार ने आते ही रोक दिया। दिल्ली की जनता मुझे बार-बार कहती थी कि हमको भी शीशमहल दिखाइए। मीडिया के बहुत सारे लोगों ने भी हमें कहा कि हमको शीशमहल लेकर चलिए। तो ऐसे में अंदर के सारे सामान और वस्तुओं के पैसे कहां खर्च हुए, उन सभी के प्राइस टैग लगाए गए हैं। तो हर प्राइस टैग के साथ उसका बिल नंबर भी लिखा हुआ है।'

प्रवेश वर्मा ने कहा, 'जब दिल्ली में कोविड चल रहा था, पूरे देश में कोविड की लहर थी, तब तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन थे। दिल्ली में एक महीने में 22 हजार मौतें होती थीं। दिल्ली के श्मशान घाटों में लकड़ी नहीं मिलती थी। चिता जलाने के लिए जगह नहीं मिलती थी। उस समय सत्येंद्र जैन कोई अस्पताल बनाने के लिए सिफारिश नहीं करते थे, कोई दवाई खरीदने के लिए अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड नहीं लिखते थे। मगर शीशमहल का काम एक भी दिन न रुके, इसके लिए फाइल पर लिखते थे कि यह बहुत जरूरी है। दिल्ली में लॉकडाउन लगा था, और शीशमहल का काम एक दिन भी नहीं रुका। ऐसे तत्कालीन दिल्ली सरकार के आदेश थे।'

उन्होंने कहा, 'जहां पर चिताएं जल रही थीं, जहां पर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वहीं पर केवल केजरीवाल और उनके परिवार को चिंता थी कि कैसे वियतनाम से मार्बल खरीदा जाए। कैसे करोड़ों रुपए के पर्दे, कैसे देश के बड़े-बड़े शोरूम से फर्नीचर लिए जाएँ, खरीदे जाएं। कोई मेड इन स्पेन है, तो कोई मेड इन इटली है। मेड इन वियतनाम है। शीशमहल खोलने का एक ही मकसद है कि जनता को सच्चाई खुद अपनी आंखों से देखनी चाहिए। जनता यहां पर आए और अपनी आंखों से देखे।'

बता दें कि सरकार द्वारा लगाए गए डिस्प्ले में 11 लाख रुपए के झूमर से लेकर 5.69 लाख रुपए के पर्दों तक की जानकारी दी गई है। हर सामान पर उसका प्राइस टैग और बिल नंबर लिखा है, ताकि जनता खुद देख सके कि किस चीज पर कितना पैसा खर्च हुआ।

निवास के बाहर लगाया गया एक बोर्ड संपत्ति पर कुल खर्च 58,83,66,314 रुपए (लगभग 58.83 करोड़ रुपए) दिखाता है। सरकार ने भवन में इस्तेमाल की गई विभिन्न वस्तुओं की कीमतों को उजागर करने वाले डिस्प्ले भी लगाए हैं, जिनमें फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सजावटी सामान शामिल हैं।



आगंतुकों और मीडिया कर्मियों को अंदर का हिस्सा दिखाया गया, जिसमें कई वस्तुओं के लिए अलग-अलग कीमत विवरण प्रदर्शित किए गए थे, जिनमें टेलीविजन, 5,58,885 रुपये के स्क्वायर सोफे, डाइनिंग टेबल और कुर्सियां, 10 लाख रुपये की गोल साइड टेबल, 1,96,482 रुपये का डबल बेड, पर्दे और कंसोल यूनिट शामिल हैं।

प्रदर्शित खर्चों में, एक कंसोल की कीमत 3,34,484 रुपये थी, जबकि पर्दे 5,69,162 रुपए के बताए गए। डिस्प्ले में निवास के विभिन्न हिस्सों और उनके अंदरूनी हिस्सों पर किए गए खर्च को भी उजागर किया गया।

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने संविधान दिवस फोटो प्रदर्शनी का किया उद्घाटन

नई दिल्ली, एजेंसी।
दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट में संविधान दिवस फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे गणराज्य की जीवंत आत्मा है, जिसका निर्माण हमारे संविधान निर्माताओं की सामूहिक बुद्धिमत्ता, त्याग और कलात्मक विरासत से हुआ है।

इस प्रदर्शनी का आयोजन अधिवक्ता परिषद, दिल्ली प्रांत (पटियाला हाउस कोर्ट इकाई) द्वारा नई दिल्ली बार एसोसिएशन के सहयोग से किया गया। उद्घाटन समारोह में विधिक समुदाय के सदस्य, विद्यार्थी एवं आम नागरिक उपस्थित रहे। औपचारिक उद्घाटन के बाद विजेंद्र गुप्ता ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने प्रदर्शित दुर्लभ ऐतिहासिक चित्रों एवं विभिन्न दृश्य सामग्रियों का बारीकी से निरीक्षण किया तथा आयोजकों से इस प्रदर्शनी में समाहित ऐतिहासिक तथ्यों और उनके महत्व पर चर्चा की।

गुप्ता ने अधिवक्ता परिषद और नई दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल के माध्यम से भारत के लोकतंत्र की आधारशिला से जुड़े इतिहास को विधिक क्षेत्र के पेशेवरों, युवा कानून विद्यार्थियों और आम नागरिकों तक सीधे पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा



कि संविधान सभा की बहसों, आदर्शों और संविधान की मूल पांडुलिपि के पीछे निहित कलात्मक उत्कृष्टता का पुनरावलोकन नागरिक दायित्व की भावना को गहरा करता है तथा दैनिक सार्वजनिक जीवन में संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ बनाता है।

गुप्ता ने संविधान सभा की चर्चाओं की कालजयी प्रासंगिकता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा में विधिक समुदाय के निरंतर योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि दुर्लभ अभिलेखीय तस्वीरों, संविधान की मूल पांडुलिपि में की गई कलात्मक चित्रकारी और उन गुमनाम अग्रदूतों की प्रेरक कहानियों को एक साथ प्रस्तुत करना भारत के संवैधानिक इतिहास और भावी पीढ़ियों के बीच एक अमूल्य सेतु का कार्य करता है।

गुप्ता ने कहा कि जब युवा अधिवक्ता और विद्यार्थी इन ऐतिहासिक पैनलों के सामने खड़े होते हैं, तो वे केवल अतीत को नहीं देख रहे होते, बल्कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे उन मूल्यों से भी जुड़ रहे होते हैं, जिन्हें हमारे राष्ट्र की भावी यात्रा का मार्गदर्शन करना चाहिए।

'भारत के संविधान का निर्माण, उसकी मूल पांडुलिपि की कला और इसे आकार देने वाले व्यक्तित्व' विषय पर केंद्रित इस प्रदर्शनी में लगभग 50 दृश्य एवं जीवनीपरक पैनल प्रदर्शित किए गए हैं। ये पैनल 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक से लेकर 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किए जाने तक की लगभग तीन वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाते हैं।

इस अवसर पर बृजेंद्र चाहर (वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अपर सॉलिसिटर जनरल), चेतन शर्मा (अपर सॉलिसिटर जनरल), हरि बोरीकर संगठन सचिव उत्तर क्षेत्र अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद तथा संजय पोद्दार (अध्यक्ष, अधिवक्ता परिषद, दिल्ली प्रांत) सहित विधिक जगत के अनेक व्यक्ति उपस्थित रहे।

इस प्रदर्शनी के माध्यम से आगंतुकों को न केवल संविधान की मूल पांडुलिपि की कलात्मक भव्यता को देखने, बल्कि उन व्यक्तित्वों और सामूहिक प्रयासों को समझने का अवसर मिला, जिन्होंने इस ऐतिहासिक दस्तावेज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस के कलात्मक मार्गदर्शन में तैयार किए गए ये चित्र भारत की सभ्यतागत यात्रा, सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक व्यक्तित्वों तथा स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रसंगों को सुंदर रूप में चित्रित करते हैं।

प्रदर्शनी के दौरान अधिवक्ता अदिति द्राल ने अतिथियों को इन चित्रों के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने चित्रों में दर्शाई गई ऐतिहासिक घटनाओं, महान व्यक्तित्वों एवं सांस्कृतिक परंपराओं के साथ-साथ संविधान के विभिन्न भागों से उनके संबंध को भी रोचक ढंग से प्रस्तुत किया।

प्रदर्शनी के समापन समारोह में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमित शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉ. विजय कुमार दहिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटियाला हाउस न्यायालय सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

दिल्ली से बिहार के 18 रुटों पर सीधी बस सेवा शुरू, पटना-गया समेत देखें सभी स्टॉपेज की लिस्ट



नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली से बिहार के 18 रुटों के लिए बस सेवा शुरू होगी। इसके लिए शुक्रवार को दिल्ली सरकार और बिहार सरकार के बीच समझौता किया गया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट अंतरराज्यीय बस अड्डा से दिल्ली- बिहार बस सेवा को रवाना की। इस अवसर पर बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत और दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह भी उपस्थित थे।

बसों के प्रमुख पड़ाव इस प्रकार हैं-

1. अररिया से दिल्ली: फोर्ब्सगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चकिया, गोपालगंज, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा और नोएडा।



2.बिहारशरीफ से दिल्ली: पटना, आरा, बक्सर, आजमगढ़, लखनऊ, आगरा और नोएडा।

3.भागलपुर से दिल्ली: मुंगेर, फतुहा, मोहनिया, वाराणसी, कानपुर, आगरा, नोएडा और दिल्ली।

4.बक्सर से दिल्ली: आजमगढ़, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद और हापुड़।

5.दरभंगा से दिल्ली: मुजफ्फरपुर, आरा, मोहनिया, वाराणसी, फतेहपुर, इटावा, मथुरा, नोएडा और दिल्ली।

6.पूर्वी चंपारण से दिल्ली: मोतिहारी, गोपालगंज, गोरखपुर, लखनऊ, हावड़ा, मथुरा, नोएडा और दिल्ली

7.गया से दिल्ली: दाउदनगर, बक्सर, लखनऊ, नोएडा और दिल्ली।

8.गया से दिल्ली: औरंगाबाद, मोहनिया, कानपुर, इटावा, आगरा, नोएडा और दिल्ली।

9.किशनगंज से दिल्ली: पूर्णिया, बेगूसराय, आरा, मोहनिया, वाराणसी, कानपुर, मथुरा, नोएडा और दिल्ली।

10.मधुबनी से दिल्ली: दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा और दिल्ली।

11. मुजफ्फरपुर से दिल्ली: मोतिहारी, गोपालगंज, गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा, नोएडा और दिल्ली।

12.मुजफ्फरपुर से दिल्ली: हाजीपुर, आरा, मोहनिया, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, नोएडा और दिल्ली।

13.नवादा से दिल्ली: गया, जीटी, डोभी, औरंगाबाद, चंदौली, आगरा, नोएडा और दिल्ली।

14.पटना से दिल्ली: आरा, बक्सर, लखनऊ, आगरा, मथुरा, नोएडा और दिल्ली।

15.पटना से दिल्ली: आरा, मोहनिया, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, इटावा, आगरा, मथुरा, नोएडा और दिल्ली।

16.पटना से दिल्ली: छपरा, सिवान, आजमगढ़, लखनऊ, अलीगढ़, नोएडा और दिल्ली।

17.पटना से दिल्ली: मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, गोपालगंज, गोरखपुर, लखनऊ, मथुरा, नोएडा और दिल्ली।

18.पूर्णिया से दिल्ली: फोर्ब्सगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा और दिल्ली।

एनसीआर में बढ़ी ठिठुरन, पारा 10 डिग्री से नीचे; अगले दो दिनों में घने कोहरे का अलर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी।
नई दिल्ली, 27 नवंबर (वेब वार्ता)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सर्दियों ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है और पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। अब सिर्फ सुबह और शाम ही नहीं, बल्कि दिन के समय भी ठिठुरन भरी ठंड का एहसास होने लगा है।

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, अगले दो दिनों में एनसीआर के लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। आज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में अधिकतम पारे में भी गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे दिन की गर्मी भी कम होगी और ठंड बढ़ेगी। शहर की आबोहवा की बात करें तो फिलहाल हवा की गुणवत्ता 'ऑरेंज जोन' में बनी हुई है, यानी प्रदूषण का स्तर मध्यम से खराब श्रेणी में है, जिससे लोगों को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार, 27 नवंबर को आसमान में हल्का कोहरा (शैलो फॉग) रहेगा। अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 28 नवंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और मध्यम कोहरा (मॉडरेट फॉग) छाने की संभावना है। तापमान में मामूली गिरावट आएगी। अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। 29 नवंबर को कोहरे का असर जारी रहेगा और मध्यम कोहरा देखने को मिलेगा। तापमान 25 डिग्री (अधिकतम) और 10 डिग्री (न्यूनतम) के आसपास बना रहेगा।

ऐसे ही 30 नवंबर को महीने के आखिरी दिन भी मध्यम कोहरा परेशान करेगा। तापमान में और गिरावट दर्ज होगी, अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 1 दिसंबर की शुरुआत भी कोहरे के साथ होगी। मध्यम कोहरा छाया रहेगा और तापमान 23 डिग्री (अधिकतम) से 9 डिग्री (न्यूनतम) तक गिर सकता है। 2 दिसंबर को मौसम विभाग के मुताबिक, इस दिन हल्का कोहरा रहेगा, लेकिन ठंड बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है।

दिल्ली में बिना पासपोर्ट-वीजा के रह रहे एक ही परिवार के 6 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए

नई दिल्ली, एजेंसी।
दिल्ली पुलिस के नॉर्थ जिले ने बड़ा हिंदू राव में संयुक्त अभियान चलाकर बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के दिल्ली में रह रहे 6 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। यह इंटेलिजेंस आधारित संयुक्त अभियान एंटी-नारकोटिक्स सेल, स्पेशल टास्क फोर्स और फॉरेनर्स सेल, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट द्वारा बड़ा हिंदू राव में चलाया गया।

सत्यापन के दौरान सभी 6 लोगों की बांग्लादेशी नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज मिले और उन्हें रिकॉर्ड में रखा गया। मेडिकल जांच के बाद सभी 6 लोगों को 26 नवंबर को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ), दिल्ली के सामने पेश किया गया। आगे की कार्यवाही तक सभी 6 लोगों की आवाजाही को सेवा सदन, शहजादा बाग, सराय रोहिल्ला तक सीमित कर दिया गया है।

दिल्ली में विदेशी नागरिकों के संदिग्ध अवैध ठहराव की विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए एंटी-नारकोटिक्स सेल (एएनसी), स्पेशल टास्क फोर्स (एटीएफ) और फॉरेनर्स सेल, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की संयुक्त टीम ने उनकी पहचान, राष्ट्रीयता और आव्रजन स्थिति का सत्यापन करने के लिए अभियान चलाया।

गुप्त सूत्र से मिली जानकारी पर कार्रवाई करते हुए एएनएफ, एसटीएफ और फॉरेनर्स सेल, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की संयुक्त टीम का गठन किया गया। पूछताछ के दौरान जहांगीर हुसैन ने बताया कि वह बांग्लादेशी नागरिक है और अपने परिवार के साथ बिना वैध यात्रा और आव्रजन दस्तावेजों के भारत में रह रहा था। टीम ने बाद में उसके परिवार के पांच सदस्यों को भी ढूंढा और सत्यापन के लिए हिरासत में लिया।

टीम ने सभी छह व्यक्तियों की बांग्लादेशी राष्ट्रीयता साबित करने वाले दस्तावेज हासिल किए और उन्हें रिकॉर्ड में रखा। सत्यापन में पाया गया कि वे बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के भारत में रह रहे थे। सत्यापन की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, सभी छह व्यक्तियों की अरुणा आसफ अली अस्पताल, दिल्ली में मेडिकल जांच की गई। 26 नवंबर को उन्हें आगे की कार्यवाही के लिए एफआरआरओ, दिल्ली के सामने पेश किया गया।

राष्ट्रीयता सत्यापन दस्तावेजों और प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच के बाद, एफआरआरओ, दिल्ली ने आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 की धारा के साथ-साथ आव्रजन और विदेशी आदेश, 2025 के पैराग्राफ 8 का हवाला देते हुए प्रतिबंध आदेश जारी किया। आदेश के अनुपालन में, आगे की कार्यवाही तक सभी छह व्यक्तियों की आवाजाही को सेवा सदन, शहजादा बाग, सराय रोहिल्ला, दिल्ली तक सीमित कर दिया गया है।

जिन 6 लोगों को पकड़ा गया है,



उनमें मो. जहांगीर हुसैन (50), कोहिनूर (40), नूर मोहम्मद (20), आसिफ (18) और दो नाबालिग सदस्य शामिल हैं। परिवार दिल्ली के सदर बाजार के आजाद मार्केट इलाके में रहता पाया गया। उनका स्थायी पता गांव त्रिपुरडी, डाकघर अमीनपुर, थाना सोनारगांव, जिला नारायणगंज, बांग्लादेश दर्ज किया गया।

सम्पादकीय

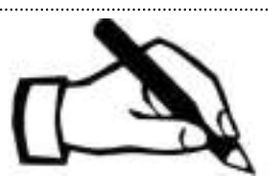

संसद का विस्तार, राज्यों के अधिकारों का सम्मान

भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी विशालता, विविधता और संघीय संरचना इसे अन्य लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से अलग पहचान देती है। देश की बढ़ती जनसंख्या, सामाजिक विविधता और शासन की बदलती आवश्यकताओं के बीच संसद की कार्यक्षमता को अधिक प्रभावी बनाना समय की मांग है। इसी संदर्भ में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा परिसीमन के सूत्र में संशोधन, लोकसभा की सदस्य संख्या में लगभग 50 प्रतिशत विस्तार का प्रस्ताव तथा वर्ष 2051 तक राज्यों की संसद में हिस्सेदारी सुरक्षित रखने की पहल एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और संवैधानिक विषय बनकर सामने आई है।

लोकसभा देश की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च निर्वाचित संस्था है। वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं। यदि इसकी सदस्य संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव लागू होता है, तो संसद में लगभग 800 से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए स्थान तैयार हो सकता है। इससे प्रत्येक सांसद के ऊपर बढ़ते जनसंख्या दबाव को कम करने और नागरिकों की समस्याओं को संसद तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का अवसर मिल सकता है। लेकिन इस प्रस्ताव का महत्व केवल सीटों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व, समानता और संघीय संतुलन को बनाए रखना होना चाहिए।

परिसीमन का मूल सिद्धांत जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण है। समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि और उसके भौगोलिक वितरण में बदलाव के कारण निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। इससे मतदाताओं की संख्या और सांसदों के प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। हालांकि, भारत जैसे संघीय देश में परिसीमन केवल जनसंख्या का गणित नहीं है, बल्कि यह राज्यों के राजनीतिक अधिकारों, विकास की दिशा और राष्ट्रीय एकता से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है।

विशेष रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में परिसीमन को लेकर चिंता रही है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों ने परिवार नियोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। इन राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए लंबे समय तक प्रयास किए हैं। यदि परिसीमन में केवल जनसंख्या को आधार बनाकर सीटों का पुनर्वितरण किया जाता है, तो अपेक्षाकृत कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों की संसद में हिस्सेदारी घटने की आशंका उत्पन्न हो सकती है। दूसरी ओर, उत्तर भारत के अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ सकती है।

सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय करने का समय

कांतिलाल मांडोत

सोशल मीडिया आज सूचना, संवाद और जनजागरण का एक प्रभावशाली माध्यम बन चुका है। दुनिया के किसी भी कोने में घटने वाली घटना कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। डिजिटल माध्यमों ने समाचारों के प्रसार को गति दी है, लेकिन इसी तेजी के साथ फेक न्यूज, भ्रामक सूचनाओं, नफरत फैलाने वाले संदेशों और बिना तथ्य जांचे प्रसारित सामग्री की चुनौती भी गंभीर होती जा रही है। ऐसे में सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी केवल तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रह सकती। समाज और नागरिकों की सुरक्षा के प्रति उनकी जवाबदेही तय करना समय की आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इसी दिशा में डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर नामक कानून के माध्यम से सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी बढ़ाने की पहल की है। इस कानून के तहत कंपनियों को हानिकारक सामग्री की पहचान कर उसे रोकने और हटाने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी। अब केवल किसी उपयोगकर्ता की शिकायत आने के बाद कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि प्लेटफॉर्म को अपने स्तर पर भी संभावित जोखिमों की निगरानी करनी होगी। महिलाओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाली सामग्री, हिंसा को बढ़ावा देने वाले संदेश, बच्चों के लिए नुकसानदेह सामग्री और मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कंटेंट पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी कंपनियों पर होगी।

इस व्यवस्था में डिजिटल प्लेटफॉर्म के डिजाइन और एल्गोरिदम से पैदा होने वाले जोखिमों को कम करने पर भी जोर दिया गया है। सोशल मीडिया कंपनियां अपने एल्गोरिदम के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उनकी रुचि के अनुसार सामग्री दिखाती हैं। कई बार यही व्यवस्था किसी व्यक्ति को लगातार उत्तेजक, भ्रामक या नकारात्मक सामग्री देखने के लिए प्रेरित करती है। उपयोगकर्ताओं को यह अधिकार देने की पहल भी महत्वपूर्ण है कि वे एल्गोरिदम आधारित सुझावों को स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं। इससे डिजिटल मंचों पर नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास होगा।

ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित व्यवस्था के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। कानून के दायरे में सोशल मीडिया, गेमिंग प्लेटफॉर्म, एप और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित संवाद सेवाएं भी आ सकती हैं। छोटे और कम जोखिम वाले कारोबारों को कुछ छूट देने की संभावना के साथ बड़ी कंपनियों की जवाबदेही तय करने का प्रयास किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया पहले ही बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर कठोर कदम उठा चुका है। इससे स्पष्ट है कि डिजिटल दुनिया में बच्चों और नागरिकों की सुरक्षा को सरकारें गंभीरता से लेने लगी हैं।

ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए गए हैं। उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर उनके वैश्विक कारोबार के आधार पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान है। भारत में भी सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायतों का निपटारा करने, आपत्तिजनक सामग्री पर कार्रवाई करने और निर्धारित दायित्वों का पालन करने की जिम्मेदारी दी गई है।

जिम्मेदारी पूरी करना

व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारियां को समझता है तब वह उसे पूरा करने की भी सोचता है अगर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां को पूरा नहीं करता इसका मतलब यह कतई नहीं है कि वह व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझता नहीं है। अक्सर होता यह है कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां को पूरा तो करना चाहता है , पर उसके पास पर्याप्त साधन नहीं होते है, इससे वह व्यक्ति और लोगों के मन में खटकने लगता है।



करिश्मा गुज्जर (खारी)

संविधान दिवस पर संविधान, बाकी दिन राजनीति

सचिन कुमार गौतम

26 नवंबर को भारत संविधान दिवस मनाता है, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। दोनों दिन अलग-अलग ऐतिहासिक उपलब्धियों की स्मृति में मनाए जाते हैं: 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अंगीकार किया था, और 26 जनवरी 1950 को वह लागू हुआ था। संविधान दिवस की शुरुआत 2015 में हुई, जब बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयंती थी।

देश में एक नहीं, बल्कि हर दिन संविधान दिवस जैसा होना चाहिए। यह इसलिए कि भारत का लोकतंत्र, नागरिक अधिकार, न्यायिक व्यवस्था और संघीय ढांचा संविधान की रक्षा में ही टिका हुआ है। संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं है; यह उस राजनीतिक समझौते का प्रतीक है जिसने विविधता भरे देश को एक साझा नागरिक अस्मिता दी।

बाबासाहेब आंबेडकर समेत संविधान सभा के सदस्यों ने देश की धार्मिक, भाषायी, जातीय, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता को ध्यान में रखकर संविधान का मसौदा तैयार किया। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि नए स्वतंत्र भारत के हर नागरिक को बराबरी, स्वतंत्रता और सम्मान की गारंटी दी जाए। संविधान ने इसी विचार को मूल अधिकारों, समानता के अधिकार और संवैधानिक संरक्षण के रूप में स्थापित किया।

आर्थिक असमानता उस समय भी थी और आज कई मायनों में और गहरी हो चुकी है। लेकिन संविधान की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि नागरिक अधिकार आर्थिक स्थिति से तय नहीं होते। गरीब हो या धनी, किसी भी नागरिक को कानून के समक्ष समान अधिकार और संरक्षण प्राप्त है। यही संविधान निर्माताओं की सबसे बड़ी देन है। इसलिए उन्हें याद करने, सम्मान देने और संवैधानिक मूल्यों को जीने के लिए हर दिन संविधान दिवस मनाने में कोई हर्ज नहीं। संविधान दिवस की घोषणा 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने की थी। तब बाबासाहेब आंबेडकर की 125वीं जयंती थी, इसलिए यह निर्णय प्रतीकात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण माना गया। सरकार का तर्क था कि इस दिवस से नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और डॉ. आंबेडकर तथा संविधान सभा के सदस्यों के योगदान को सम्मान मिलेगा।

26 नवंबर पहले राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। कानून का पालन भी



संविधान के प्रति सम्मान का ही एक रूप है, क्योंकि कानून की वैधता अंततः संविधान से लेती है। इसलिए नाम बदलने से मूल भावना बदलनी नहीं चाहिए थी–कि संविधान केवल उत्सव का विषय नहीं, बल्कि शासन और नागरिक व्यवहार का मापदंड है।

भाजपा के लिए यह मुद्दा नागरिक अधिकारों और संविधान की रक्षा से अधिक राजनीतिक भी रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके समर्थक वर्गों ने कई अवसरों पर संविधान की धारणाओं, विशेषकर धर्मनिरपेक्षता और कुछ संवैधानिक प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं। ऐसे माहौल में सत्ता में आने के बाद भाजपा के लिए यह जरूरी था कि वह कम से कम प्रतीकात्मक स्तर पर संविधान के प्रति सम्मान दिखाए। 2015 में आंबेडकर जयंती का अवसर इसके लिए उपयुक्त लगा होगा। बहरहाल, यदि अंबेडकर का नाम लेना 'फैशन' बन गया है, तो यह बुरा नहीं है। कम से कम इससे संविधान, उसके निर्माताओं और सामाजिक न्याय के विचार को याद रखने की प्रक्रिया जारी रहती है। अमित शाह के उस बयान का जिक्र भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अंबेडकर-अंबेडकर कहना फैशन बन गया है। यदि यह फैशन संविधान के प्रति जागरूकता लाए, तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन संविधान के प्रति सम्मान केवल भाषण, लेख या समारोह से नहीं आंका जाता। उसे संसदीय प्रक्रिया, न्यायपालिका के स्वतंत्र कार्यसंचालन, प्रेस की स्वतंत्रता, विपक्ष के अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रता और संवैधानिक संस्थाओं की मजबूती से परखा जाता है। संविधान दिवस का असली सम्मान तभी होता है जब सत्ता में बैठे लोग अपनी आलोचना सहने और विरोध को लोकतांत्रिक अधिकार मानने को तैयार रहें। 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष ने संविधान को केंद्रीय मुद्दा बनाया। इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया कि भाजपा की बड़ी बहुमत वाली सरकार बनते ही संविधान में बदलाव की कोशिश हो सकती है। यह केवल राजनीतिक आरोप नहीं था; कुछ भाजपा नेताओं और सांसदों ने भी इस आशय के बयान दिए कि 400 सीटें चाहिए ताकि संविधान बदला जा सके। इससे जनता में संवैधानिक सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हुई। चुनाव परिणाम ने यह संदेश स्पष्ट किया कि जनता ने संविधान के प्रति खतरे को गंभीरता से लिया। भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई और उसे सरकार बनाने के लिए गठबंधन साझेदारों के सहारे की जरूरत पड़ी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगी नेताओं का समर्थन न होता, तो नरेन्द्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना संभव नहीं होता। इस परिणाम ने यह भी दिखाया कि संविधान केवल चुनावी नारा नहीं, बल्कि मतदाताओं के लिए विश्वास का विषय बन चुका है।

इस वर्ष संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 1949 में संविधान के अंगीकरण और राष्ट्र की प्रगति में उसकी भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संविधान के कारण ही एक साधारण परिवार के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला।

यह बात आंशिक रूप से सही है। संविधान ने सामाजिक पृष्ठभूमि को राजनीतिक अवसर की बाधा नहीं बनने दिया। लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह और डॉ. मनमोहन सिंह जैसे नेता भी साधारण परिवारों से आए थे। इसलिए 'साधारण' होने का दावा केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रखा जा सकता। साथ ही, मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले तीन बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे। उनके राजनीतिक उत्थान में संगठन, चुनावी तंत्र और समर्थन आधार की भूमिका भी थी। इसलिए केवल साधारण परिवार से आने को प्रधानमंत्री बनने का एकमात्र कारण नहीं कहा जा सकता। लेख में मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और कहा कि 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। लेकिन यह भी सवाल उठता है कि जिन 80 करोड़ लोगों को अब भी मुफ्त राशन की जरूरत है, उनकी स्थिति कब सुधरेगी। गरीबी से बाहर आने और राशन सुरक्षा पर निर्भर रहने के बीच का अंतर स्पष्ट करना जरूरी है। संविधान केवल अधिकार देता है; सरकार का कर्तव्य है कि वह उन अधिकारों को आर्थिक और सामाजिक वास्तविकता में बदले।

कैसे पढें आत्मकथा?

डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल

सार्वजनिक जीवन में सोनिया गांधी की सुदीर्घ और प्रभावशाली उपस्थिति ने उनकी आत्मकथा में हमारी दिलचस्पी बहुत बढ़ा दी है और उसके बाजार में आते ही चर्चाओं का बाज़ार भी गर्म हो गया है। लगता है जैसे पूरा भारतीय समाज दो खेमों में बंट गया है, लेकिन इस पूरे प्रसंग को केवल सोनिया गांधी के राजनीतिक समर्थन या विरोध के चश्मे से देखना शायद उचित नहीं होगा।

दूसरों के जीवन में झांकना मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है और आत्मकथा हमें यह मौका देती है। यदि आत्मकथा किसी ऐसे व्यक्ति की हो जिसका सार्वजनिक जीवन, राजनीति और सत्ता के गलियारों से जुड़ा रहा हो तो यह उत्सुकता कई गुना बढ़ जाती है। पाठक केवल उसके जीवन की कहानी नहीं जानना चाहते, वे उन घटनाओं के भीतर झांकना चाहते हैं जिनके वे स्वयं भी किसी-न-किसी रूप में साक्षी रहे हैं। सोनिया गांधी की सद्य-प्रकाशित आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लॅव' को लेकर भी कुछ ऐसा ही माहौल है।

सार्वजनिक जीवन में सोनिया गांधी की सुदीर्घ और प्रभावशाली उपस्थिति ने उनकी आत्मकथा में हमारी दिलचस्पी बहुत बढ़ा दी है और उसके बाजार में आते ही चर्चाओं का बाज़ार भी गर्म हो गया है। लगता है जैसे पूरा भारतीय समाज दो खेमों में बंट गया है, लेकिन इस पूरे प्रसंग को केवल सोनिया गांधी के राजनीतिक समर्थन या विरोध के चश्मे से देखना शायद उचित नहीं होगा। यह अवसर आत्मकथा नाम की एक महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा और उसे पढ़ने के हमारे तौर-तरीकों पर विचार करने का भी है। आत्मकथा आखिर है क्या? क्या वह अपने जीवन का सिलसिलेवार ब्यौरा है? क्या वह घटनाओं, व्यक्तियों और तारीखों का ऐसा विवरण है जिसे इतिहास की किताब की तरह परखा जा सके? या वह अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखने, समझने और उसका अर्थ तलाशने की एक कोशिश है? वस्तुतः आत्मकथा इन सबका मिला-जुला रूप हो सकती है, लेकिन सबसे पहले वह लेखक का अपने जीवन के साथ संवाद है। इसमें घटनाएं जितनी महत्वपूर्ण हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है उन घटनाओं को देखने वाला व्यक्ति, उसकी स्मृतियां, उसकी संवेदनाएं और उसका दृष्टिकोण।

इस विधा की खूबी यह है कि इसमें व्यक्ति अपने समय, परिवेश, संबंधों, सफलताओं और असफलताओं को अपने ढंग से देखता/देखती है। वह चाहे तो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करे, अपनी भूलों पर पछताए, अपनी उपलब्धियों का बखान करे या कुछ अनुभवों को निजी रखे। आत्मकथा का कोई एक अनिवार्य ढांचा नहीं है। न ही यह आवश्यक है कि हर आत्मकथाकार अपने जीवन के प्रत्येक प्रसंग पर समान विस्तार से बात करे।

दुनिया की अनेक प्रसिद्ध आत्मकथाएं इस विविधता की साक्षी हैं। महात्मा गांधी की 'सत्य के प्रयोग' में उनकी नैतिक और आध्यात्मिक यात्रा के साथ कमजोरियों, भूलों और प्रयोगों का भी उल्लेख है। इसका महत्व इस बात में है कि गांधी स्वयं को किस निर्ममता से परखने का प्रयास करते थे। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा 'मेरी कहानी' में एक व्यक्ति के बौद्धिक विकास के साथ अपने समय की राजनीति और राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक परिदृश्य उपस्थित होता है।

हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा-श्रृंखला- 'क्या भूलूं क्या याद करूं,' 'नीड़ का निर्माण फिर,' 'बसेरे से दूर' और 'दशद्वार से सोपान तक' निजी जीवन, परिवार, प्रेम और साहित्य के अनेक रंग सामने लाती है। अमृता प्रीतम की 'रसीदी टिकट' एक स्त्री के निजी अनुभवों और संवेदनाओं की बेबाक अभिव्यक्ति है। इसी क्रम में प्रभा खेतान की 'अन्या से अनन्या' और मन्नू भंडारी की 'एक कहानी यह भी' को याद किया जा सकता है। इन्हीं के साथ याद की जा सकती हैं दलित आत्मकथाएं भी, जिनमें ओमप्रकाश वाल्मीकि की 'जूठन' प्रमुख है।

विदेशी आत्मकथाओं में रूसो की 'कन्फैशन्स' का उल्लेख जरूरी है, जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व के उन पक्षों को भी सामने रखा जिन्हें छिपाना अधिक सुविधाजनक हो सकता था। बेंजामिन फ्रैंकलिन की 'आत्मकथा' आत्म-निर्माण, श्रम और सार्वजनिक जीवन की कहानी है। नेल्सन मंडेला की 'लांग वाक टू फ्रीडम' में एक व्यक्ति का संघर्ष, दक्षिण अफ्रीका की मुक्ति और नस्लभेद के विरुद्ध आंदोलन की कथा से जुड़ जाता है। माया एंजेलो की 'आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स' निजी अनुभवों के माध्यम से नस्लीय भेदभाव, स्त्री होने की चुनौतियों और आत्मसम्मान की लड़ाई का चित्र उभारती है।

इस संदर्भ में अपने समाज की ओर देखें तो एक विचित्र स्थिति दिखाई देती है। हम दूसरों के जीवन में गहरी दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन अपने बारे में कुछ कहने की बात आती है तो सहज नहीं रह जाते। अपनी कमजोरियों, असफलताओं, ईर्ष्याओं, महत्वाकांक्षाओं, गलत निर्णयों और निजी संबंधों के अंतर्विरोधों को सार्वजनिक करना हमें कठिन लगता है। इसके पीछे हमारे सामाजिक संस्कार भी हैं। हमारे यहां व्यक्ति की प्रतिष्ठा अक्सर परिवार और समुदाय की प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है। अपने बारे में कुछ ऐसा कह देना जो परिवार की स्थापित छवि के अनुकूल न हो, पूरे परिवार को असहज कर सकता है। अपनी गलती स्वीकार करना भी सहज मानवीय व्यवहार के बजाय कमजोरी समझ लिया जाता है।

ऐसे में संभव है, लेखक कुछ प्रसंगों को जानबूझ कर छोड़ दे या उन्हें इस तरह प्रस्तुत करे कि उसकी अपनी छवि पर आंच न आए, लेकिन क्या इससे उसकी आत्मकथा को पढ़ने और समझने की हमारी जिज्ञासा और जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है? क्या किसी आत्मकथा में आत्मरक्षा या आत्म-औचित्य की प्रवृत्ति दिखाई देने पर उसे एक झटके में खारिज कर देना चाहिए? संभव है, यह भी लेखक के व्यक्तित्व और उसकी आत्मदृष्टि को समझने का एक सूत्र हो। यहां आत्मकथा और इतिहास के बीच का अंतर समझना जरूरी है। आत्मकथा इतिहास की पुस्तक नहीं है, हालांकि इतिहास के अध्ययन के लिए वह महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध करा सकती है। इतिहासकार अनेक स्रोतों, दस्तावेजों और परस्पर विरोधी विवरणों की जांच करता है। आत्मकथाकार अपने अनुभवों और स्मृतियों के सहारे अतीत को देखता है। स्मृति कोई कैमरा नहीं है जो हर घटना को उसी रूप में सुरक्षित रखे।

कैमरे का भी कोई-न-कोई एंगल होता है। समय के साथ कुछ घटनाएं धुंधली पड़ती हैं, कुछ अधिक स्पष्ट हो जाती हैं और कुछ का अर्थ बदल जाता है। यहीं से आत्मकथा को पढ़ने का सलीका सामने आता है। हमें यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि लेखक ने क्या लिखा है, न कि इस बात पर नाराज होना चाहिए कि उसने क्या नहीं लिखा। उसने किसी घटना को किस तरह देखा, किन प्रसंगों को महत्व दिया, किन्हें छोड़ दिया और अपने जीवन के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला, इन सब पर विचार किया जा सकता है। उसकी स्थापनाओं से असहमति भी हो सकती है, लेकिन यह सोचना कि वह अपनी आत्मकथा में वही सब लिखेगा जिसकी हम उम्मीद करते हैं, उसके साथ अन्याय होगा। हर व्यक्ति को अपने जीवन की निजता और अपने अनुभवों के चयन का अधिकार है। कोई व्यक्ति अपने जीवन के सभी प्रसंग सार्वजनिक करने के लिए बाध्य नहीं है। किसी आत्मकथा में किसी प्रसंग का उल्लेख न होना उस प्रसंग के बारे में किसी निष्कर्ष का आधार नहीं बन सकता।

उप्र की सियासत के साये में सिसकता सवर्ण स्वाभिमान

डॉ. शैलेश शुक्ला

सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़कर समाज को देखने वाली राजनीति ने उत्तर प्रदेश को हमेशा जातीय समीकरणों के चश्मे से देखा है और इस चश्मे में सवर्ण समाज की तस्वीर सबसे अधिक धुंधली, सबसे अधिक उपेक्षित और सबसे अधिक गलत ढंग से अंकित की गई है। यह वह समाज है जिसने इस प्रदेश की संस्कृति को भाषा दी, साहित्य को सृजन दिया, शिक्षा को परम्परा दी, न्याय को नैतिकता दी और स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व दिया, किन्तु आज वही समाज अपने ही प्रदेश में अपने ही स्वाभिमान के लिए सिसकता हुआ दिखाई देता है। सियासत ने उसे कभी वोट बैंक नहीं माना, क्योंकि वह बँटकर वोट नहीं करता, वह विचार करके मतदान करता है और इसी विचारशीलता की उसे सबसे बड़ी सजा मिली है। जिस समाज ने कभी किसी से कुछ माँगा नहीं, उसी समाज को आज सबसे अधिक अनसुना किया जा रहा है। यह लेख किसी जाति या किसी समुदाय के विरोध में नहीं है, यह तो उस मौन अन्याय के विरुद्ध है जो संविधान की आड़ में, समानता के नाम पर और सामाजिक न्याय के नारे के नीचे निरंतर सवर्णों के साथ किया जा रहा है।

संविधान ने हमें समानता का वचन दिया था, किन्तु व्यवहार में समानता का अर्थ ही बदल दिया गया। संविधान की मूल आत्मा यह थी कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, किन्तु आज जन्म के आधार पर ही यह तय हो जाता है कि किसे अवसर मिलेगा और किसे अवसर से वंचित किया जाएगा। एक ही परीक्षा, एक ही मेरिट, एक ही योग्यता, किन्तु दो अलग-अलग कट-ऑफ, दो अलग-अलग अवसर और दो अलग-अलग भविष्य, यह कैसी समानता है? एक सवर्ण युवक जो रात-रात भर पढ़कर, माँ-बाप की गाढ़ी कमाई लगाकर, ट्यूशन और किताबों के बोझ तले दबकर परीक्षा देता है, वह जब कुछ अंकों से चयन से वंचित हो जाता है और उससे कम अंक पाने वाला उसका सहपाठी व्यवस्था की कृपा से चयनित हो जाता है, तो उसके मन में व्यवस्था के प्रति जो अविश्वास पैदा होता है, उसे कोई भी राष्ट्रवादी विचारक अनदेखा नहीं कर सकता। यह अविश्वास केवल एक युवक का नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का मौन आक्रोश है।

यह आक्रोश हिंसा नहीं चाहता, यह आरक्षण का विरोध नहीं करता, यह तो केवल इतना पूछता है कि योग्यता को कब तक दंडित किया जाएगा और जन्म को कब तक पुरस्कृत किया जाएगा। जब योग्यता हारती है, तो राष्ट्र हारता है और जब राष्ट्र की प्रतिभा पलायन करती है, तो इसका दोष उस प्रतिभा को नहीं, उस व्यवस्था को दिया जाना चाहिए जिसने उसे अपने ही देश में पराया कर दिया। सवर्णों के साथ हो रहे संवैधानिक अन्याय का दूसरा सबसे बड़ा रूप आर्थिक आधार पर भेदभाव का अभाव है। गरीबी की कोई जाति नहीं होती, भूख का कोई वर्ण नहीं होता, बेरोजगारी का कोई गोत्र नहीं होता, किन्तु हमारे नीति-निर्माताओं ने गरीबी को भी जाति के खानों में बाँट दिया है। एक दलित गरीब, एक पिछड़ा गरीब और एक सवर्ण गरीब, तीनों की पीड़ा एक जैसी है, तीनों के आँसू एक जैसे हैं, तीनों के बच्चों की भूख एक जैसी है, फिर सहायता का पैमाना अलग-अलग क्यों है? सवर्ण गरीब के लिए न छात्रवृत्ति है, न शुल्क में छूट है, न छात्रावास में स्थान है, न नौकरी में संरक्षण है, न व्यवसाय के लिए विशेष योजना है। वह गरीब होकर भी गरीब नहीं माना जाता, क्योंकि उसके नाम के आगे एक विशेषण लगा दिया गया है, सवर्ण। क्या यही सामाजिक न्याय है कि गरीब को उसकी गरीबी के कारण नहीं, उसकी जाति के कारण सहायता से वंचित कर दिया जाए? आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान एक स्वागत योग्य कदम अवश्य था, किन्तु व्यवहार में वह भी अनेक स्थानों पर कागजी रह गया है। प्रमाण-पत्रों की जटिलता, आय की अव्यावहारिक सीमा, नौकरियों में उसका अपूर्ण क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में उसका टकराव, इन सबने उस राहत को भी अधूरी कर दिया है। एक सवर्ण कल्याण की चिंता करने वाला विचारक यह मानता है कि सहायता का आधार गरीबी होना चाहिए, जाति नहीं और जब तक यह सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक सामाजिक न्याय अधूरा ही रहेगा।

आज सवर्ण समाज को जिस सबसे गहरी पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है, वह है उसे दोयम दर्जे का नागरिक मानने की मानसिकता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सवर्ण नागरिक का कर्तव्य तो पूर्ण है, किन्तु अधिकार आधे हैं। उसे कर देना है, कानून मानना है, राष्ट्र की सेवा करनी है, सीमा पर बलिदान देना है, आपदा में सबसे आगे खड़ा होना है, किन्तु जब अधिकार की बात आती है, तो उसे पीछे धकेल दिया जाता है। उसके मंदिरों का चढ़ावा सरकार के नियंत्रण में है, किन्तु अन्य धर्मस्थलों की व्यवस्था को स्वायत्तता प्राप्त है। उसके पर्वों पर ध्वनि, जुलूस और आयोजन के लिए अनुमति की लंबी प्रक्रिया है, किन्तु अन्य आयोजनों के लिए वही कठोरता नहीं दिखाई देती। उसके महापुरुषों को पाठ्यपुस्तकों से धीरे-धीरे हटाया जा रहा है, उसके इतिहास को विकृत किया जा रहा है, उसकी परम्पराओं को पिछड़ापन कहकर उपहास उड़ाया जा रहा है। जब कोई सवर्ण अपनी पीड़ा कहता है, तो उसे जातिवादी कह दिया जाता है, जब वह अपने अधिकार की बात करता है, तो उसे सामंतवादी कह दिया जाता है और जब वह अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहता है, तो उसे संविधान विरोधी कह दिया जाता है। यह कैसी विडम्बना है कि जिस समाज ने संविधान बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, उसी समाज को आज संविधान के नाम पर ही चुप करा दिया जाता है।

इस पीड़ा की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि सवर्णों को आज राज्य की दृष्टि में केवल करदाता के रूप में देखा जा रहा है। सवर्ण समाज का एक बड़ा वर्ग व्यापारी है, किसान है, शिक्षक है, अधिवक्ता है, चिकित्सक है, उद्यमी है, नौकरीपेशा है, जो ईमानदारी से आयकर देता है, जीएसटी देता है, संपत्ति कर देता है, सड़क कर देता है और उसी कर से चलने वाली योजनाओं का लाभ उसे सबसे कम मिलता है। वह कर देता है तो सड़क बनती है, विद्यालय बनता है, छात्रवृत्ति बँटती है, आवास मिलता है, किन्तु जब वह स्वयं अपने बच्चे की फीस के लिए सहायता माँगता है, तो उसे बताया जाता है कि वह सामान्य वर्ग से है, इसलिए वह पात्र नहीं है। क्या राष्ट्र का निर्माण केवल कर देने वालों के कर्तव्य से होगा और लाभ लेने वालों के अधिकार से होगा? क्या यह न्यायसंगत है कि जो सबसे अधिक देता है, उसे सबसे कम मिले और जो सबसे कम देता है, उसे सबसे अधिक मिले? एक कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व है कि वह करदाता के साथ कृतज्ञता का व्यवहार करे, न कि उसे शोषण का साधन समझे।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक विजय कुमार द्वारा ओ.एस. पब्लिकेशन, बी-2542, नरेला, इंडस्ट्रियल एरिया, नार्थ वेस्ट दिल्ली-110040 से मुद्रित कराकर 1536/108 गणेशपुरा रोड, त्रीनगर दिल्ली-110035 से प्रकाशित। सम्पादक : विजय कुमार RNI No. : DELHIN/2015/66886
अखबार में प्रकाशित तथ्यों एवं लेखों से सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं, किसी भी कानूनी वाद विवाद का निपटारा दिल्ली न्यायालय के अधीन होगा। मोबाइल : 9210092542 फोन :- 011-46696546 E-mail : opensearchdelhi@gmail.com

सपा के कार्यकाल पर योगी का हमला : बोले- युवाओं को माफिया-नकल की पहचान देने वालों से हिसाब मांगना चाहिए

गोंडा (एजेंसी)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को शहीदे आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में समाजवादी पार्टी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने सपा के घोषणापत्र और पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल को कठघरे में खड़ा करते हुए युवाओं से विपक्ष से उसके कामकाज का हिसाब मांगने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग आज बड़े-बड़े वादे और घोषणाएं कर रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने युवाओं को कितनी नौकरियां दीं, किसानों के लिए क्या किया, नारी शक्ति के लिए क्या कदम उठाए और प्रदेश के विकास के लिए उनका योगदान क्या रहा? शहीदे आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में आयोजित टैबलेट वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की पहचान नकल माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया और वसूली सिंडिकेट से थी।



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों की पहचान नकल माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया और वसूली सिंडिकेट से थी। नौकरी का विज्ञापन निकलते ही वसूली करने वाले सक्रिय हो जाते थे। युवाओं की प्रतिभा को सम्मान नहीं मिलता था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकारों की एक ही उपलब्धि थी- 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया'।

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में 2017 से पहले के गोंडा और देवीपाटन मंडल की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि पहले गोंडा की पहचान गंदे शहरों में होती थी। बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने मंडल के विकास के लिए करीब 36 हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। गोंडा में मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज के निर्माण तथा श्रावस्ती में एयरपोर्ट तैयार होने को विकास की उपलब्धियों के रूप में गिनाया।

युवाओं को नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाला बनने का संदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित होने से युवा अब नौकरी पाने वाले ही नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले भी बन रहे हैं। हर जिले में सरदार वल्लभभाई पटेल स्किलिंग एंड एंप्लॉयमेंट जोन बनाने की योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार से जोड़ा जाएगा। जापान और जर्मनी में नौकरी के इच्छुक युवाओं को भाषा प्रशिक्षण देकर विदेश भेजने की योजना भी बताई। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह सहित अन्य विधायक व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

युवा की मेहनत को सम्मान, प्रतिभा को अवसर और सपनों को मिले नई उड़ान, यही डबल इंजन सरकार का संकल्प : सीएम योगी

लखनऊ (एजेंसी)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवचयनित 201 लेखा परीक्षकों और 1,393 सहायक लेखाकारों समेत कुल 1,594 युवाओं को नियुक्ति-पत्र सौंपने से पहले उन्हें उज्ज्वल भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने कहा कि हर युवा की मेहनत को सम्मान, प्रतिभा को अवसर और सपनों को नई उड़ान मिले, यही डबल इंजन सरकार का संकल्प है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। इसी संकल्प के साथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश (वित्त विभाग) के अंतर्गत नवचयनित 201 लेखा परीक्षकों और 1,393 सहायक लेखाकारों सहित कुल 1,594 युवाओं को नियुक्ति-पत्र वितरित किए जाएंगे।' सीएम योगी ने अपने पोस्ट में लिखा, 'हर युवा की मेहनत को सम्मान, प्रतिभा को अवसर और सपनों को नई उड़ान मिले, यही डबल इंजन सरकार का संकल्प है।'

इसके साथ ही उन्होंने पिछली सरकारों पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा, 'वर्ष 2017 से पहले सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद ने युवाओं के विश्वास को चोट पहुंचाई थी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री शुक्रवार को 46,800 छात्रों को टैबलेट बांटेंगे। उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, 'लखनऊ में युवाओं के परिश्रम को नियुक्ति का सम्मान मिलेगा, तो जनपद गोंडा में 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना' के अंतर्गत गोंडा, बहराइच, बलरामपुर व श्रावस्ती के 46,800 विद्यार्थियों और प्रशिक्षणार्थियों को टैबलेट प्रदान कर उनके सपनों को डिजिटल सामर्थ्य मिलेगा। उन्होंने अपनी पोस्ट के आखिर में लिखा, सभी नवचयनित युवाओं को हार्दिक बधाई और उज्ज्वल भविष्य की अग्रिम शुभकामनाएं।

राजेश सजवाण ने पलायन की राह छोड़ सेब की बागवानी को बनाया आजीविका का आधार

जगत सागर बिष्ट

नई टिहरी : पहाड़ में रोजगार के सीमित अवसरों के चलते जनपद के जौनपुर विकासखंड के ग्राम मीरीया, पट्टी लालूर निवासी राजेश सजवाण को भी कभी आजीविका की तलाश में अपना गांव छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा था। वहां वह होटल में नौकरी कर परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे। इसी बीच उत्तराखंड सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उद्यान विभाग के सहयोग से उन्हें गांव में ही स्वरोजगार की नई राह मिली। एप्पल मिशन योजना का लाभ लेकर वह शहर की नौकरी छोड़कर गांव लौटे और सेब की बागवानी को अपनी आजीविका का माध्यम बनाया और पहाड़ में स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता की एक प्रेरणादायक मिसाल पेश कर रहे हैं। घ्राजेश सजवाण बताते हैं कि वर्ष 2021-22 में उन्होंने एप्पल मिशन योजना के तहत 500 सेब के पौधे लगाए। इसके बाद वर्ष 2023-



24 में 500 और पौधों का रोपण किया। इस प्रकार उन्होंने कुल 1000 सेब के पौधों से बागवानी की शुरुआत की। योजना के तहत सरकार की ओर से 80 प्रतिशत अनुदान मिला, जबकि 20 प्रतिशत धनराशि उन्होंने स्वयं खर्च की।

शुरुआत में क्षेत्र के लोग यहां सेब की बागवानी की सफलता को लेकर आशंकित थे, लेकिन राजेश ने मेहनत और लगन से अपना प्रयास जारी रखा। घ्आज उनकी यह पहल क्षेत्र में बदलाव की मिसाल बन गई है। राजेश बताते हैं कि उनकी बागवानी से प्रेरित होकर आसपास के क्षेत्र में 100 से अधिक सेब के बगीचे विकसित हो चुके हैं। वर्तमान में उनके साथ 8 से 10 लोगों को गांव में ही रोजगार मिल रहा है। इससे स्थानीय लोगों को घर के आसपास ही आजीविका का साधन उपलब्ध हो रहा है। वहीं, राजेश की सालाना आय भी लगभग 8 से 10 लाख रुपये तक पहुंच गई है। घ्राजेश बताते हैं कि पहले गांव और आसपास के खेतों में पानी की भारी किल्लत रहती थी। इसके समाधान के लिए लघु सिंचाई विभाग और उत्तराखंड सरकार के सहयोग से सोलर वाटर लिफ्टिंग पंप स्थापित कराया गया। इससे खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचने लगा। आज जिन खेतों में पानी के अभाव में खेती करना मुश्किल था, वहां मटर, शिमला मिर्च और टमाटर सहित विभिन्न सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। इससे किसानों को खेती के नए विकल्प मिले हैं और बारिश पर निर्भरता भी कम हुई है।

संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर मनोज झा बोले-'मानसून सत्र कब खत्म हुआ'

पटना (एजेंसी)

महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों पर भी उन्होंने पलटवार किया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत में मनोज झा ने केंद्र द्वारा बुलाए गए संसद सत्र पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र अभी तक समाप्त ही नहीं हुआ है।

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'कभी सुना है कि जाड़े के मौसम में मानसून चल रहा हो? यह कौन सी चाणक्य नीति है? आप क्या चाहते हैं, लोकतंत्र का गला घोंटकर रख दें?' मनोज झा ने कहा कि यह परिसीमन नहीं बल्कि लोकतंत्र को कमजोर करने का अभियान है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के विनाश की दिशा में उठाया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो असम में कर चुकी है, वही अब पूरे देश में करना चाहती



है, जो कतई स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार के पास एक बढ़िया प्रेशर कुकर है। अमित शाह उस कुकर की सीटी तय करते हैं लेकिन जब लोकतंत्र और जनता सीटी बजाएगी तो कान फट जाएगा। अमित शाह के उस बयान पर कि महिला आरक्षण विधेयक को राहुल गांधी नहीं रोक पाएंगे, मनोज झा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। राष्ट्रपति ने इसे अधिसूचित कर दिया है और यह राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। ऐसे में फिर से इसे लाने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि यह पाखंड दर्शाता है कि इसके पीछे कुछ ऐसा है, जिस पर पर्दा डाला जा रहा है।

संसद सत्र पर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का केंद्र पर हमला, बोले - सच्चाई से भाग रही है सरकार

पटना (एजेंसी)

संसद के विशेष सत्र को लेकर बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह सत्र तो बहुत पहले आना चाहिए था। लेकिन सरकार ने उसे लेट कर दिया। सरकार को डर लगा रहता है, वह सच का सामना नहीं करना चाहती और सच्चाई से भागती है। पप्पू यादव ने कहा कि अब जबरदस्ती का सत्र बुलाया जा रहा है। कानून और हर चीज को हिटलर की तरह लागू करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को संसद में चर्चा से भागने की बजाय लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहिए। महिला आरक्षण बिल को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि यह बिल पहले ही पास हो चुका है। इसे कांग्रेस और भाजपा, दोनों की सहमति से लाया गया था। सोनिया गांधी और कांग्रेस हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं, जबकि भाजपा इसे



सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे के रूप में इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले ही महिला बिल पास करा चुकी है, तो अब इसे दोबारा लाने की क्या जरूरत है।

उन्होंने परिसीमन के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि परिसीमन के लिए देश की सहमति लेने की जरूरत है, कांग्रेस की सहमति लेने की जरूरत है, लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं करती, इसका जवाब उसे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े फैसले को अकेले नहीं थोपा जा सकता, इसके लिए सबको साथ लेकर चलना होगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा जोड़-तोड़, ईडी, सीबीआई और धनबल से जनबल को कमजोर कर रही है। वह दूसरी पार्टियों को तोड़ रही है, डरा रही है और फंसा रही है। इसके कारण भारत का लोकतंत्र लगातार कमजोर होता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब पूरी लोकसभा को चोरी करके सत्ता हथियाने की कोशिश की जा रही है। पप्पू यादव ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है, जिसके एजेंडे में चौबीस घंटे, चौबीस मिनट और चौबीस सेकंड सिर्फ सत्ता है। संविधान, देश और 140 करोड़ जनता उसके एजेंडे में नहीं है। उसके एजेंडे में बस यही है कि चाहे चोरी करके हो, धनबल से हो, ईडी से हो या सारी संस्थाओं को खत्म करके हो, सत्ता बनी रहनी चाहिए, चाहे इसके लिए कोई भी पाप करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आनंद मोहन को एक महीने के भीतर सरेंडर करने के आदेश पर भी पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह कैसा कानून है।

बिहार : पुलिस की सुरक्षा में सेंध! नाबालिग के अपहरण का आरोपी कोर्ट से फरार, हथकड़ी सरकाकर पुलिस को दिया चकमा

मुजफ्फरपुर (एजेंसी)

मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट से शुक्रवार की शाम एक बंदी हथकड़ी सरकाकर फरार हो गया। आरोपी को साहेबगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। फरार बंदी की पहचान मिंटू कुमार मलिक के रूप में हुई है। वह जिले के पारू थाना क्षेत्र के रामपुर केशों मालही गांव का रहने वाला है और एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोपी था। कोर्ट परिसर से बंदी के फरार होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। साहेबगंज थाना पुलिस ने अपहरण के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान वह पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी सरकाते हुए फरार हो गया। कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपी के फरार होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बंदी के फरार होने के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद स्थानीय पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और उसकी खोजबीन शुरू की। कोर्ट में मौजूद प्रत्यक्षदर्शी राजू कुमार ने बताया कि वह अपनी दुकान पर थे। इस दौरान कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में लोग और अधिवक्ता मौजूद थे। तभी उन्होंने देखा कि एक पुलिसकर्मी बंदी को लेकर जा रहा था। इसी दौरान बंदी हथकड़ी सरकाकर पुलिस को चकमा देते हुए भाग गया। इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिसकर्मी उसकी तलाश में लग गए, लेकिन वह पकड़ में नहीं आ सका। इस पूरे मामले में साहेबगंज थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोपी को गुरुवार को पारू थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था।

पीडीए जन पत्र में महिलाओं-युवाओं के लिए वादे, महिलाओं को मिलेंगे 40 हजार रुपये : फखरुल हसन चांद

लखनऊ (एजेंसी)

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने पार्टी के पीडीए घोषणा पत्र, महिलाओं और युवाओं के लिए किए गए वादों तथा कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं, बेटियों और युवाओं के हितों को प्राथमिकता दी है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी संविधान में विश्वास रखने वाले हर नागरिक का सम्मान करती है।

पीडीए घोषणा पत्र को लेकर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो 'जन पत्र' जारी किया है, उसमें महिलाओं को 40 हजार रुपये देने का वादा किया गया है। इसके अलावा इंटरमीडिएट पास करने वाली बेटियों को 36 हजार रुपये देने, घर में बेटी के जन्म पर सोना देने और



युवाओं को लैपटॉप उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। उन्होंने कहा कि युवतियों के लिए 'कन्या विद्या धन' देने की भी घोषणा की गई है। इन घोषणाओं का उद्देश्य महिलाओं और युवाओं को आर्थिक तथा शैक्षणिक रूप से मजबूत करना है। संविधान और पीडीए की विचारधारा पर बात करते हुए सपा प्रवक्ता ने कहा कि उनकी पार्टी बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हर उस व्यक्ति का सम्मान करती है, जो भारतीय संविधान में आस्था रखता है। व्यक्ति की वेशभूषा, दाढ़ी या पहनावे से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि देश का हर नागरिक सम्मान का अधिकारी है और समाजवादी पार्टी ने हमेशा सभी वर्गों के हितों के लिए काम किया है। इसी सोच के तहत पार्टी ने पीडीए का नारा दिया है।

उन्होंने कहा कि शोषित और पीड़ित वर्ग के लोग इस विचारधारा के साथ खड़े हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर फखरुल हसन चांद ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर इमरान मसूद की किसी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती। उन्होंने खड़गे के उस बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह टेलीविजन देखते हैं और वहां प्रसारित होने वाली बातों को सुनते हैं। वहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों दलों का गठबंधन पहले से कायम है और वे विपक्षी इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। फिलहाल दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सीटों का बंटवारा जल्द तय हो जाएगा। इस संबंध में दूसरे दौर की बातचीत भी जारी है और दोनों दलों का राष्ट्रीय नेतृत्व इस प्रक्रिया को लेकर सकारात्मक है।

बिहार : परिसीमन विधेयक पर आरजेडी में दो फाड़! लालू-तेजस्वी के विरोध के बीच सांसद सुरेंद्र यादव ने किया समर्थन

गयाजी (एजेंसी)

परिसीमन संशोधन विधेयक को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के भीतर सियासी मतभेद उभरते नजर आ रहे हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जहां इस विधेयक के विरोध में खड़ा बताया जा रहा है। वहीं, जहानाबाद से राजद सांसद डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव ने खुलकर इसके समर्थन में बयान देकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है।

उनके इस रुख से पार्टी के भीतर दो अलग-अलग विचार सामने आने लगे हैं। गयाजी में मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने परिसीमन विधेयक को जरूरी बताते हुए कहा कि वह इसके पक्षधर हैं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत पार्टी के कई नेता इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। राजद के लोकसभा सांसदों के बीच इस मुद्दे पर अलग-अलग राय होने की चर्चा है। जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव विधेयक के समर्थन में हैं, जबकि पाटलिपुत्र से सांसद मीसा भारती और बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह के विरोध में रहने की बात सामने आ रही है। वहीं, औरंगाबाद से राजद सांसद अभय कुशवाहा के भी परिसीमन विधेयक के समर्थन में आने की चर्चा है। हालांकि, इन सांसदों के रुख को लेकर पार्टी की ओर से कोई औपचारिक सामूहिक घोषणा नहीं की गई है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सेवा तीर्थ में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में परिसीमन संशोधन विधेयक और महिला आरक्षण कानून से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सीटों में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की योजना है। सरकार के इस कदम के बाद देश की राजनीति में परिसीमन को लेकर बहस तेज हो गई है।

उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 28 अधिकारियों के तबादले

लखनऊ(एजेंसी)

उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) स्तर के 28 अधिकारियों का तबादला किया। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। फेरबदल के तहत आईपीएस मोहित अग्रवाल को वाराणसी पुलिस आयुक्त के पद से हटाकर प्रयागराज का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनकी जगह किरण एस. को वाराणसी का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है। वह इससे पहले लखनऊ रेंज में पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) के पद पर तैनात थे। गाजियाबाद के पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड़ को नोएडा का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया



गया है। वहीं, प्रयागराज के पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया को हटाकर एडीजी (स्थापना) बनाया गया है।

नोएडा की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह को गाजियाबाद का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, एडीजी बरेली जोन रामित शर्मा को एडीजी लखनऊ जोन और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार को एडीजी बरेली जोन नियुक्त किया गया है। आईजी अलीगढ़ रेंज प्रभाकर चौधरी को आईजी लखनऊ रेंज बनाया गया है। अयोध्या के एसएसपी गौरव ग्रोवर को मुरादाबाद का एसएसपी नियुक्त किया गया है, जबकि सतपाल को अयोध्या का नया एसएसपी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का यह फेरबदल उत्तराखंड सरकार की ओर से 17 आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों के तबादले के एक दिन बाद हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने अधिकारियों को जिलों, खुफिया इकाइयों, पीएसी बटालियनों और विशेष शाखाओं में नई जिम्मेदारियां सौंपी थीं। उत्तराखंड में नैनीताल के एसएसपी मंजुनाथ टीसी को 31वीं पीएसी बटालियन, रुद्रपुर का कमांडेंट नियुक्त किया गया है। वहीं, रुद्रपुर स्थित 46वीं पीएसी बटालियन के कमांडेंट पंकज भट्ट को आईआरबी-1, बैलपड़ाव का कमांडेंट बनाया गया है। खुफिया विभाग में तैनात पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा को ऊधम सिंह नगर का एसएसपी नियुक्त किया गया है।

मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में लापरवाही पर होगी कार्रवाई, कम फॉर्म जमा करने वाले बीएलओ के काम का होगा स्थलीय सत्यापन

नोएडा (एजेंसी)

गौतमबुद्धनगर जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान-2027 (एसएसआर) के तहत मतदाता सूची को दुरुस्त करने और अधिक से अधिक पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए निर्वाचन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में मंडलायुक्त मेरठ मंडल एवं रोल ऑब्जर्वर भानु चंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में अभियान की प्रगति, नए मतदाताओं के पंजीकरण, दावों एवं आपत्तियों, ऑफलाइन प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन और आगामी 28 व 29 नवंबर को आयोजित होने वाले विशेष अभियान दिवसों की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई।



मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को केवल निर्धारित लक्ष्य पूरा करने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि व्यापक जनसंपर्क और जनजागरूकता के माध्यम से प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुंच बनाई जाए। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं सहित ऐसे सभी नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाए, जिनका नाम अभी तक सूची में शामिल नहीं है। इसके लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने पर जोर दिया गया।

अभियान की वास्तविक प्रगति और बीएलओ के कार्यों की गुणवत्ता परखने के लिए मंडलायुक्त ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम प्रपत्र प्राप्त करने वाले बीएलओ को चिह्नित करने के निर्देश दिए। 27 नवंबर को संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सुपरवाइजर स्वयं ऐसे बीएलओ के क्षेत्रों में जाकर स्थलीय सत्यापन करेंगे। अधिकारियों को निर्धारित घरों में पहुंचकर रैंडम आधार पर जांच करने को कहा गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बीएलओ ने वास्तव में घर-घर जाकर संपर्क किया है या नहीं। विशेष अभियान दिवसों के बाद भी लगभग 100 बीएलओ के कार्यों का सत्यापन कराया जाएगा। मंडलायुक्त ने सभी लंबित ऑफलाइन प्रपत्रों को निर्धारित समयसीमा में शत-प्रतिशत डिजिटाइज करने और प्रतिदिन शाम छह बजे तक रिपोर्ट लॉक करने के निर्देश दिए।

साथ ही ईआरओ-नेट पर दर्ज आंकड़ों और बीएलओ से प्राप्त सूचनाओं का नियमित मिलान करने तथा किसी भी तरह की विसंगति मिलने पर तत्काल उसका समाधान कराने को कहा। बैठक में मंडलायुक्त ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विधानसभा क्षेत्र और मतदेय स्थलवार बीएलओ की अद्यतन सूची तथा उनके मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

संक्षिप्त समाचार

मिस्र में तेल टैंकर में आग, 31 की मौत :21 से ज्यादा घायल; कई गाड़ियां भी जलीं



काहिरा, एजेंसी। मिस्र की राजधानी काहिरा के पास हाईवे पर बुधवार रात एक तेल टैंकर में आग लग गई। इसकी चपेट में आने से 24 से ज्यादा कारें और बाइक जल गईं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हादसे में 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 21 से ज्यादा घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया था। इसके बाद उसमें जोरदार धमाका हुआ और आग फैल गई। जलती गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे की सूचना मिलते ही दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाई। स्थानीय लोगों ने भी घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। अब आग पर काबू पा लिया गया है। हादसा काहिरा के उपनगर इम्बाबा के वाराक जिले में हुआ, जहां आग तेजी से कई कारों में फैल गई। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल-फतह अल-सीसी ने पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई। घायलों को ज़ायद स्पेशलाइज्ड, इम्बाबा जनरल और वर्राक सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बचाव अभियान में 39 एम्बुलेंस लगाई गई हैं। मिस्र में हर साल सड़क हादसों में हजारों लोगों की मौत होती है। तेज रफ्तार, खराब सड़कों और ट्रैफिक नियमों का सही तरीके से पालन न होना इन दुर्घटनाओं की प्रमुख वजह हैं। इसी साल जनवरी में बेनी सुएफ प्रांत के पास कई गाड़ियों की भीषण टक्कर में 21 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 16 घायल हुए थे।

नाइजीरिया में 22.6 करोड़ डॉलर की मेथामफेटामाइन जब्त

नाइजीरिया , एजेंसी। नाइजीरिया की मादक पदार्थ निरोधक एजेंसी ने बुधवार को देश के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में बड़ी कार्रवाई करते हुए कम से कम 22 करोड़ डॉलर मूल्य की मेथामफेटामाइन जब्त की। इस मामले में पांच मैक्सिकन नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। नेशनल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने बताया कि उसके अधिकारियों ने एनुगु राज्य में बड़े पैमाने पर चल रही एक अवैध प्रयोगशाला पर छापा मारा। यहां से मेथामफेटामाइन बनाने में विशेषज्ञता रखने वाले पांच मैक्सिकन नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। एजेंसी के प्रवक्ता फेमी बाबाफेमी ने एक बयान में बताया कि इन लोगों को कथित तौर पर एक नाइजीरियाई नागरिक ने भर्ती किया था। वे फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश में दाखिल हुए थे। बाबाफेमी ने कहा, 'अवैध रूप से संचालित इस फैक्टरी से कुल 1,512 किलोग्राम मेथामफेटामाइन बरामद की गई। इसमें तैयार और निर्माणाधीन दोनों तरह की नशीली दवाएं शामिल हैं। इनकी अनुमानित कीमत 22.68 करोड़ डॉलर है। इस साल देश में की गई सबसे बड़ी जब्तियों में से यह एक है। नाइजीरिया अवैध मादक पदार्थों के कारोबार का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। इसी साल मई में दक्षिण-पश्चिमी नाइजीरिया में नाइजीरियाई और मैक्सिकन नागरिकों से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया गया था। हाल के दिनों में इस तरह की कई कार्रवाइयां की गई हैं।

जापान : जंगली सब्जियों के लिए हजारों डॉलर खर्च कर रहे लोग

टोक्यो, एजेंसी। ऑर्गेनिक खानपान और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति बढ़ते वैश्विक रुझान ने जापान की सदियों पुरानी जंगली सब्जियां चुनने की परंपरा को नया आकर्षण बना दिया है। यहां पर्यटक जंगलों और पहाड़ों में प्राकृतिक रूप से उगने वाली सब्जियां जुटाने के लिए विशेष टूर और कार्यशालाओं पर सैकड़ों से लेकर हजारों डॉलर तक खर्च कर रहे हैं। 'सानसाई' नाम से पहचानी जाने वाली इन मौसमी पहाड़ी सब्जियों के प्रति दिलचस्पी बढ़ रही है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में सानसाई की परंपरा हजारों साल पुरानी है। वसंत ऋतु में पहाड़ों और जंगलों में उगने वाले इन पौधों की 280 से अधिक किस्में बताई जाती हैं।

अमेरिका ने 10 लाख एआई उपग्रहों के लिए स्पेसएक्स की योजना को मंजूरी दी

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी नियामकों ने स्पेसएक्स को अंतरिक्ष में डेटा सेंटर के रूप में काम करने वाले 10 लाख तक उपग्रह तैनात करने की अनुमति दे दी है। खगोलविदों ने इस पर आपत्ति जताई है और चेतावनी दी है कि इस परियोजना से शोध कार्यों में बाधा आ सकती है और रात को आसमान का स्वरूप बदल सकता है। फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (एफसीसी) ने कहा कि प्रस्तावित 'स्टारमाइंड' नेटवर्क पृथ्वी पर इस्तेमाल के लिए अंतरिक्ष में डेटा प्रोसेस करेगा, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कंप्यूटिंग की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसे अंतरिक्ष में डेटा सेंटरों के एक समूह के लिए अमेरिका की ओर से दी गई पहली मंजूरी बताया गया है। इस मंजूरी से नेटवर्क को स्थापित करने की अनुमति मिलती है; इसका मतलब यह नहीं है कि उपग्रह (पहले ही लॉन्च किए जा चुके हैं।

ये उपग्रह ऑप्टिकल लिंक के जरिए कम्युनिकेट करेंगे, जबकि रेडियो लिंक बैकअप और आपातकालीन संचार के रूप में काम करेंगे। एफसीसी ने कहा कि यह सिस्टम अंतरिक्ष में मौजूद कचरे से जुड़े उनके नियमों के अनुरूप है।

चेयरमैन ब्रेंडन कैर ने कहा, 'अमेरिका दुनिया को 'सुपर इंटेलिजेंस' के युग में ले जा रहा है।



राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में, अमेरिका यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है कि यह क्रांतिकारी तकनीक नए अवसर पैदा करे, निवेश को बढ़ावा दे और अमेरिकी लोगों को लंबे समय तक लाभ पहुंचाए। '

उन्होंने कहा, 'एफसीसी ने आज अंतरिक्ष में डेटा सेंटरों के लिए 10 लाख 'ऑर्बिटल कंप्यूट मॉड्यूल' तैनात करने की मंजूरी देकर इस प्रयास को और तेज कर दिया है। यह कदम अमेरिका के नेतृत्व और विकास को गति देने के लिए जरूरी कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक नई और साहसिक शुरुआत है। '

कैर ने कहा, 'सुपर इंटेलिजेंस (एसआई) के क्षेत्र में अमेरिका के नेतृत्व को बनाए रखने के लिए 'कंप्यूट कैंपस' या डेटा सेंटर बहुत जरूरी हैं। अपनी कंप्यूटिंग क्षमता को पृथ्वी से बाहर ले जाकर, स्पेसएक्स और उनके कई प्रतिस्पर्धी, जो अपने खुद के ऑर्बिटल डेटा सेंटरों पर काम कर रहे हैं, समय की मांग को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, 'यह अमेरिकी सूझबूझ का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो अंतरिक्ष और उन्नत तकनीक में हमारी ताकतों को एकजुट कर सकता है, हमारी आर्थिक बढ़त को मजबूत कर सकता है और हमारे देश में समृद्धि का विस्तार कर सकता है। एफसीसी ने बताया कि वह अंतरिक्ष में डेटा सेंटरों से जुड़े अन्य प्रस्तावों की भी समीक्षा कर रहा है और अपनी नियमित प्रक्रियाओं के तहत उन पर जल्द ही फैसला लेगा। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी' ने इस फैसले का विरोध किया है और कहा है कि वे इस मंजूरी से 'बहुत निराश और हताश' हैं। सोसाइटी ने चेतावनी दी है कि बड़े और अधिक संख्या में मौजूद उपग्रह लंबे समय तक चमकते रह सकते हैं, जिससे खगोलीय अवलोकन में बाधा आ सकती है। उन्होंने कहा कि कंप्यूटिंग उपकरणों से निकलने वाला रेडियो उत्सर्जन और गर्मी, रेडियो और इन्फ्रारेड खगोल विज्ञान को भी प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा, उन्होंने अंतरिक्ष में उपग्रहों के आपस में टकराने और लॉन्चिंग तथा वायुमंडल में दोबारा प्रवेश के कारण होने वाले प्रदूषण को लेकर भी चिंता जताई है। एक मीडिया बयान में कहा गया है, 'अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी (एएएस) इस बात से निराश और दुखी है कि फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन ने स्पेसएक्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में दस लाख (1 मिलियन) उपग्रहों का एक नेटवर्क तैनात करने का लाइसेंस दे दिया है। बयान में कहा गया है, 'जैसा कि एएएस ने पहले भी एफसीसी के सामने अपनी बात रखी थी, यह प्रस्तावित नेटवर्क (द्व) खगोलीय सुविधाओं में दशकों से किए गए सरकारी निवेश को काफी नुकसान पहुंचाएगा, और (द्वद्व) खगोलविदों तथा आम लोगों की रात के आसमान को देखने और उसका अध्ययन करने की क्षमता को प्रभावित करेगा। ' सोसाइटी ने माना कि स्पेसएक्स ने पहले खगोल विज्ञान पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए अपने 'स्टारलिंक' उपग्रहों के डिजाइन में बदलाव किए थे। सोसाइटी के अनुसार, इन बदलावों से कुछ मदद तो मिली, लेकिन समस्याएं पूरी तरह खत्म नहीं हुईं। उन्होंने दस लाख उपग्रहों वाले इस प्रस्तावित नेटवर्क को एक बिल्कुल अलग स्तर का प्रोजेक्ट बताया। सोसाइटी के अनुसार, इस लाइसेंस की शर्तों के तहत स्पेसएक्स को 2033 तक उपग्रह तैनात करना शुरू करना होगा, 2035 तक कक्षा में 1 लाख उपग्रह स्थापित करने होंगे, और 2040 तक पूरे नेटवर्क को तैनात करना होगा।

ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका: जन्म से नागरिकता छीनने की नई कोशिश पर लगाई रोक; जानें फैसले में क्या-क्या कहा

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता देने के नियमों में बदलाव करने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक और कोशिश को अदालत ने रोक दिया है। वॉशिंगटन की एक संघीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन के नए आदेश पर रोक लगाते हुए साफ कहा कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से अमेरिकी संविधान में दिए गए नागरिकता के अधिकार में नई शर्तें नहीं जोड़ सकते। इस मामले में अमेरिकी सिविल लिबर्टीज यूनियन ने प्रभावित परिवारों की ओर से अदालत में याचिका दायर की थी।

यह मामला नाथन बनाम ट्रम्प के नाम से जाना जा रहा है। ट्रंप ने 6 अगस्त को एक नया कार्यकारी आदेश जारी किया था। इसका मकसद अमेरिका में पैदा होने वाले कुछ बच्चों को जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता से बाहर रखना था। इससे पहले जून में सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के नागरिकता से जुड़े पुराने आदेश पर रोक लगा चुका था। इसके बाद प्रशासन ने नए आदेश के जरिए कुछ और श्रेणियों के बच्चों को नागरिकता के दायरे से बाहर करने की कोशिश की।

ट्रंप के नए आदेश में उन बच्चों को निशाना बनाया गया था, जिनके माता-पिता में से कोई भी अमेरिकी नागरिक नहीं है। इसमें कुछ खास श्रेणियां शामिल थीं। मसलन, ऐसे माता-पिता जिन्हें प्रशासन ने 'दुश्मन देश का विदेशी नागरिक' माना है, विदेशी सरकारों के कर्मचारी और वे लोग जो अमेरिका में बच्चे को जन्म देकर नागरिकता हासिल करने की योजना बनाते हैं। इस आदेश में उन परिवारों को भी शामिल किया गया था, जो पैसे देकर सरोगेसी के जरिए अमेरिका में बच्चे को जन्म दिलवाते हैं। यानी व्यावसायिक सरोगेसी के मामलों में पैदा हुए बच्चों की नागरिकता पर भी सवाल खड़ा किया गया था।

नए आदेश का दायरा सिर्फ विदेशी राजदूतों तक सीमित नहीं था। इसमें दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में काम करने वाले कुछ अन्य कर्मचारियों को भी शामिल किया गया था। ऐसे कर्मचारी, जो अपनी सरकारी जिम्मेदारी निभाने के लिए अमेरिका में रह रहे हैं, उनके बच्चों को भी इस आदेश के तहत नागरिकता से वंचित करने की कोशिश की गई थी। ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि इन श्रेणियों के लोग अमेरिकी संविधान के तहत मिलने वाले जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार के दायरे में नहीं आते। अदालत ने प्रशासन की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों के लिए अपनी तरफ से नागरिकता के नए अपवाद नहीं बना सकते।ष्ट्र के मुताबिक, अदालत ने माना कि अमेरिकी कानून के तहत आने वाले बच्चों को केवल उनके माता-पिता की नागरिकता या स्थिति के आधार पर जन्मसिद्ध नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता।

अंतरिक्ष में बनेंगे एआई के डेटा सेंटर: स्पेसएक्स को 10 लाख उपग्रह छोड़ने की मंजूरी; जानें कब से होगी तैनाती?

टेक्सास, एजेंसी। अंतरिक्ष में अब सिर्फ इंसान और उपग्रह ही नहीं, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के बड़े-बड़े डेटा सेंटर भी नजर आएंगे। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (एफसीसी) ने अंतरिक्ष में 10 लाख तक उपग्रह तैनात करने की मंजूरी दी है। इन उपग्रहों की मदद से अंतरिक्ष में ही डेटा सेंटर बनाए जाएंगे, जहां एआई से जुड़े जटिल काम किए जा सकेंगे। इस परियोजना का नाम 'स्टारमाइंड' रखा गया है। इसका मकसद तेजी से बढ़ती एआई की जरूरतों को पूरा करना है।

सूरज की रोशनी से चलेंगे अंतरिक्ष के डेटा सेंटर : इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रह सूरज की रोशनी से ऊर्जा हासिल करेंगे। इसी बिजली से उनमें लगे कंप्यूटर और एआई सिस्टम काम करेंगे। इन उपग्रहों पर बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण किया जाएगा और फिर जरूरी जानकारी धरती पर भेजी जाएगी। इससे जमीन पर बड़े-बड़े डेटा सेंटर बनाने की जरूरत कुछ हद तक कम हो सकती है। साथ ही बिजली और ठंडा रखने पर होने वाला खर्च भी घटने की उम्मीद है।

एफसीसी के अध्यक्ष ब्रेंडन कार ने इस फैसले को अमेरिका के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। उनका कहना है कि अमेरिका सुपर इंटेलिजेंस यानी अति विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में दुनिया की अगुवाई कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में देश इस तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में कंप्यूटिंग की क्षमता विकसित करने से निवेश बढ़ेगा, नई संभावनाएं पैदा होंगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। कार के मुताबिक, एआई के क्षेत्र में दुनिया में आगे बने रहने के लिए बड़े डेटा सेंटर बेहद जरूरी हैं। अंतरिक्ष में कंप्यूटिंग की व्यवस्था तैयार होने से अमेरिका को अपनी अंतरिक्ष और आधुनिक तकनीक की ताकत का एक साथ इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। एफसीसी की मंजूरी में उपग्रहों के बीच संपर्क और उन्हें नियंत्रित करने की व्यवस्था भी शामिल है।

ब्रिटेन: ऑक्सफोर्ड में भारतीय छात्रा से नस्लभेद, महिला बोली- 'तुमसे बदबू आती है'

ऑक्सफोर्ड, एजेंसी। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक भारतीय पीएचडी छात्रा ने नस्लभेद को लेकर अपनी आपबीती सुनाई है। उनका नाम कामाक्षी है। उन्होंने शहर में खरीदारी के दौरान अपने साथ हुई एक घटना के बारे में बताया। इसके साथ ही उन्होंने बड़े शिक्षण संस्थानों में नस्लभेद को लेकर भी अपनी बात रखी। कामाक्षी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। इसमें उन्होंने बताया कि ऑक्सफोर्ड में अलग-अलग रंग और नस्ल के लोगों को किस तरह के बुरे अनुभवों से गुजरना पड़ता है। उन्होंने यह बात पहले की एक पोस्ट पर नस्लभेदी टिप्पणी आने के बाद कही। उस टिप्पणी के बाद कई लोगों ने उनका समर्थन किया था। उन्होंने कहा, 'आप सभी मेरी तरफ से इतने नाराज थे। इससे मुझे एहसास हुआ कि ऑक्सफोर्ड



में लोगों को जिन बुरे अनुभवों का सामना करना पड़ता है, उनके बारे में आपसे बात न करके मैं आपके साथ सही नहीं कर रही थी'।

दुकान में महिला ने क्या कह दिया : कामाक्षी ने अपने साथ हुई एक खास घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वह एक स्थानीय दुकान में सामान देख रही थीं। तभी एक श्वेत महिला उनके आसपास चक्कर लगाने लगी। इससे वह काफी असहज हो गईं। कुछ देर बाद वह महिला उनके पास आई। उन पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी। कामाक्षी ने बताया, 'बाद में वह मेरे पास आई और उसने कहा। मैं उसके शब्द दोहरा रही हूं, 'मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा। तुमसे बहुत, बहुत बदबू आती है'।

इस बात से कामाक्षी हैरान रह गईं। उन्होंने कहा कि वह महिला की बात का जवाब भी नहीं दे पाई। महिला वहां से चली गई। उन्होंने कहा, 'मैं पूरी तरह हैरत में पड़ गई थी। जब तक मेरा दिमाग समझ पाता कि आखिर हुआ क्या है, तब तक वह जा चुकी थी'।

पिता के इत्र से जुड़ी थी यह बात : कामाक्षी ने बताया कि इस टिप्पणी से उन्हें खास तौर पर दुख पहुंचा। इसकी वजह उनके इत्र से जुड़ी एक निजी भावना थी। वह जिस इत्र का इस्तेमाल करती हैं, वही उनके पिता भी लगाते हैं। इस जुड़ाव से उन्हें सुकून मिलने के बजाय इस घटना ने उन्हें दुखी और परेशान कर दिया। उन्होंने बताया कि पूरे दिन वह खुद को कमतर दिखाने की कोशिश करती रहीं। वह नहीं चाहती थीं कि किसी का ध्यान उनकी तरफ जाए। कामाक्षी ने साफ किया कि दुकान में हुई यह घटना कोई अकेली घटना नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। इसमें रोजमर्रा के व्यवहार में होने वाली दुश्मनी से लेकर बड़े संस्थानों की नाकामी तक शामिल है। उन्होंने कहा, 'यह कोई अकेली घटना नहीं है। सड़कों पर छोटी-छोटी नस्लभेदी घटनाओं से लेकर संस्थान की ओर से नस्लवादियों को मंच देने तक, यह सच्चाई है कि कोई भी प्रतिष्ठित संस्थान नस्लभेदी, साम्राज्यवादी या फिर समस्याग्रस्त जड़ों से पूरी तरह मुक्त नहीं है।

अमेरिका में थैंक्सगिविंग पर तूफान का साया: न्यूयॉर्क में तेज बारिश और हवाओं का अलर्ट, न्यू जर्सी में आपातकाल

न्यूयॉर्क, एजेंसी। अमेरिका में थैंक्सगिविंग से पहले भीषण तूफानों ने छुट्टियों के जश्न और यात्रा की तैयारियों पर असर डालना शुरू कर दिया है। खराब मौसम के पूर्वानुमान के चलते न्यूयॉर्क की मशहूर मैसीज थैंक्सगिविंग डे परेड को शनिवार तक के लिए टाल दिया गया है। वहीं, फिलाडेल्फिया में आयोजकों ने मौसम संबंधी चिंताओं के कारण परेड में गुब्बारे नहीं उड़ाने का फैसला किया है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयॉर्क की मैसीज परेड शनिवार सुबह 8:30 बजे (अमेरिकी पूर्वी समय) शुरू होगी। यह फैसला भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए लिया गया है। दोनों तटों पर तूफान का असर थैंक्सगिविंग की छुट्टियों के दौरान



अमेरिका में आठ करोड़ से ज्यादा लोगों के यात्रा करने की उम्मीद है। ऐसे में पूर्वी और पश्चिमी तट पर खराब मौसम से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पूर्वी तट पर सुपरस्टॉर्म सैंडी के बाद सबसे ऊंचे जलस्तर की आशंका जताई गई है। डेलावेयर और न्यू जर्सी के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होने का खतरा है। पश्चिमी तट पर भी तटीय इलाकों में बाढ़ की आशंका बनी हुई है। सैन फ्रांसिस्को के दक्षिण में पैसिफिका इलाके में तेज लहरों के कारण एक पियर का हिस्सा ढह गया। वहीं, सैन डिएगो के आसपास ऊंचे ज्वार के कारण जलस्तर के पुराने रिकॉर्ड टूट गए।

खराब मौसम को देखते हुए एयरलाइंस ने भी यात्रियों को संभावित परेशानी के लिए आगाह किया है। साउथवेस्ट एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस ने थैंक्सगिविंग के दिन पूर्वोत्तर अमेरिका में उड़ानों के प्रभावित होने की आशंका जताई है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होकुल ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाओं और तटीय इलाकों में बाढ़ की चेतावनी दी है। उन्होंने लोगों से स्थानीय मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखने और यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। न्यू जर्सी की गवर्नर मिकी शेरिल ने भी बड़े तूफान की आशंका को देखते हुए पूरे राज्य में आपातकाल घोषित किया है। तूफान के कारण तेज और नुकसान पहुंचाने वाली हवाएं, भारी बारिश, तटीय इलाकों में बाढ़ और लंबे समय तक बिजली गुल रहने की आशंका है। यह आपातकालीन घोषणा बुधवार शाम छह बजे (अमेरिकी पूर्वी समय) से प्रभावी हुई। गवर्नर शेरिल ने छुट्टियों में यात्रा करने वाले लोगों से अपील की कि वे तूफान के सबसे खराब असर से बचने के लिए बुधवार को ही अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करें।

बांग्लादेश- अवामी लीग ने 2 दिन बंद का ऐलान किया



ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी से पहले राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। उनकी पार्टी अवामी लीग ने 27 और 28 नवंबर को देशभर में दो दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है। हसीना की पार्टी अवामी लीग ने अपने लॉकडाउन के पीछे 8 मांगें रखी हैं। इनमें पार्टी पर लगा प्रतिबंध हटाना और राजनीतिक बंदियों को रिहा करना शामिल है। वहीं, सरकार ने हसीना की वापसी और बढ़ती हिंसा को देखते हुए सीमा पर सुरक्षा भी बढ़ा दी है। इस बीच, सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर में देशभर में आगजनी की करीब 100 घटनाएं दर्ज की गई हैं।

सीमा पर बॉर्डर सेना की 108 टुकड़ियां तैनात : हसीना की वापसी से पहले तारिक रहमान सरकार ने सीमा से लगे सात जिलों में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की 108 टुकड़ियां तैनात की हैं। सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन, बॉडी कैमरों और दूसरे निगरानी उपकरणों की मदद से नजर रख रही हैं। पुलिस ने भी सीमा से लगे इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। जगह-जगह जांच चौकियां बनाई गई हैं और संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा, सीमा से लगे 30 जिलों में प्रशासन ने सुरक्षा एजेंसियों को संवेदनशील रास्तों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

15 दिन में ग्रामीण बैंक की 100 शाखाओं पर हमला : बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया रहे मुहम्मद यूनुस की ओर से बनाए गए ग्रामीण बैंक की शाखाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। बैंक की 24 नवंबर की आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक, 10 नवंबर से अब तक देशभर में इसकी करीब 100 शाखाओं पर हमले हो चुके हैं। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि अवामी लीग को कभी राजनीति नहीं करने दी जाएगी। पार्टी पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कहने-सुनने के समझौते के तहत नई दिल्ली से बातचीत जारी है। हसीना की सत्ता जाने के बाद से सरकार पर विरोध की आवाज दबाने के आरोप लग रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अगस्त 2024 से अक्टूबर 2026 के बीच पत्रकारों को गिरफ्तारी, हिंसा, मुकदमों और आर्थिक रोक का सामना करना पड़ा।

किम जोंग उन ने किया परमाणु ठिकानों का दौरा, सामरिक हथियारों के व्यापक इस्तेमाल पर रहा जोर

सोल, एजेंसी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने बुधवार को देश के परमाणु ठिकानों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने परमाणु हथियार उत्पादन क्षमता को और मजबूत करने का आह्वान किया। परमाणु सामग्री उत्पादन केंद्रों और हथियार अनुसंधान संस्थान का निरीक्षण करते हुए उन ने कहा कि देश को अलग-अलग सैन्य अभियानों में सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। दक्षिण कोरिया की समाचार एजेंसी योनहाप के अनुसार, किम ने बुधवार को इन परमाणु ठिकानों का दौरा किया। हालांकि, उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी केसीएनए ने अपनी रिपोर्ट में इन केंद्रों के नाम और उनके स्थान का खुलासा नहीं किया। निरीक्षण के दौरान किम ने कहा कि उत्तर कोरिया अपनी परमाणु सामग्री उत्पादन क्षमता का व्यवस्थित और लगातार विस्तार कर रहा है, ताकि देश के परमाणु हथियारों के जखीरे को मजबूत और आधुनिक बनाया जा सके। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों और अलग-अलग सैन्य अभियानों में सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की क्षमता विकसित करने को महत्वपूर्ण और तत्काल आवश्यकता बताया।

किम ने इसके पीछे आधुनिक युद्ध में सामरिक परमाणु हथियारों



की सैन्य उपयोगिता और उत्तर कोरिया की उस देश के साथ साझा सीमा का हवाला दिया, जिसे उन्होंने सबसे खतरनाक शत्रु देश बताया। उनका इशारा दक्षिण कोरिया की ओर था। उत्तर कोरियाई नेता ने अमेरिका पर पूर्वोत्तर एशिया में परमाणु प्रसार को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा,' अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ परमाणु हथियार साझा करने और उनके संयुक्त इस्तेमाल की व्यवस्था विकसित कर रहा है। इससे क्षेत्र में एक वैश्विक परमाणु सैन्य गठबंधन प्रणाली तैयार हो रही है। किम ने कहा कि मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों में उत्तर कोरिया के लिए अपने परमाणु हथियारों के भंडार को बढ़ाना और भी जरूरी हो गया है। उन्होंने दोहराया कि उत्तर कोरिया की परमाणु शक्ति संपन्न देश की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है और बाहरी देशों के बयानों या परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग से इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उत्तर कोरिया ने वर्ष 2023 में अपने संविधान में खुद को परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में स्थापित किया था। किम ने कहा कि परमाणु हथियारों का स्वामित्व देश की संप्रभुता और सुरक्षा की बुनियादी गारंटी है। इसे खत्म करने की किसी भी कोशिश को उत्तर कोरिया अपनी संप्रभुता पर हमला और युद्ध की घोषणा के रूप में देखेगा। इस साल फरवरी में सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की नौवीं कांग्रेस में भी उत्तर कोरिया ने अपनी परमाणु हथियार संपन्न देश की स्थिति को अपरिवर्तनीय बताया था।

उस दौरान प्योंगयांग ने पांच वर्षीय सैन्य आधुनिकीकरण योजना के तहत परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करने का संकल्प लिया था। यह किम जोंग उन का किसी परमाणु केंद्र का चौथा ऐसा दौरा है, जिसकी जानकारी सरकारी मीडिया ने सार्वजनिक की है। इससे पहले उन्होंने सितंबर 2024, जनवरी 2025 और जून 2026 में भी परमाणु प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया था।

आप पुराने नियम पर वापस जा सकते हैं', एमएसके प्रसाद ने गेंद पर लार के इस्तेमाल को लेकर गिल की मांग का समर्थन किया

नई दिल्ली (एजेंसी)

भारत के पूर्व मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट के बाद गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध को हटाने की शुभमन गिल की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि आजकल बल्लेबाजों का इतना दबदबा है कि गेंदबाजों को जो भी मदद मिल सके, वह उन्हें मिलनी चाहिए। एमएसके प्रसाद इटालिया टी10 लीग में 'वेनिस लाइववायर' के टीम डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा कि यह पाबंदी कोविड-19 महामारी के दौरान लगाई गई थी, लेकिन अब हालात बेहतर हो चुके हैं, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं रह गया है।

प्रसाद ने कहा, 'मैं वास्तव में उनके (शुभमन गिल के) साथ हूं, क्योंकि वह नियम कोविड-19 के दौर में आया था, जब लार या ऐसी अन्य चीजों के इस्तेमाल की मनाही थी। मुझे लगता है कि आप हमेशा पुराने नियम पर वापस जा सकते हैं। अब जब हालात बेहतर हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप देखें, तो हाल ही में एक मैच में 720 रन बने। गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए, कम से कम ऐसी छोटी-छोटी चीजों की तो अनुमति दी ही जा सकती है। मैं इस मामले में शुभमन गिल के साथ हूं। शुभमन गिल उन खिलाड़ियों में से एक हैं, जिनकी पहचान 2016 और 2020 के बीच प्रसाद की चयन समिति ने शुरुआती दौर में ही कर ली थी। भारतीय पुरुष टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए, प्रसाद ने बताया कि उनकी समिति ने तीन स्तरों पर भारत की 'बेंच स्ट्रेंथ' तैयार की थी, जिसमें शुभमन गिल, ऋषभ पंत और पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी शामिल थे। 'एक चयन समिति का काम और भूमिका नए टैलेंट की पहचान करना होता है। हम एक रिले रेस में दौड़ने वालों की तरह हैं, जो अगली चयन समिति को 'बैटन' (जिम्मेदारी) सौंप देते हैं।

हम उन्हें ऐसी बेंच स्ट्रेंथ देते हैं ताकि वे अगले खिलाड़ियों को तैयार कर सकें। हो सकता है कि कुछ चयनकर्ताओं ने विश्व कप न जीता हो, लेकिन उन्होंने इतनी मजबूत बेंच स्ट्रेंथ तैयार कर दी होती है कि जब अगला चयनकर्ता आता है, तो शायद उसी के कार्यकाल में विश्व कप जीत लिया जाए। 'इसलिए, चयन समिति का काम हमेशा नए टैलेंट की तलाश करना, उन्हें पहचानना और 'बेंच



स्ट्रेंथ' तैयार करना होना चाहिए, ताकि भारतीय क्रिकेट लंबे समय तक शीर्ष पर बना रहे। वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट के साथ ऐसा हो चुका है; एक दौर ऐसा आया था जब अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों या 'बेंच स्ट्रेंथ' की कमी के कारण उनके प्रदर्शन और रैंकिंग में भारी गिरावट आ गई थी। हमने काफी अच्छी 'बेंच स्ट्रेंथ' तैयार की थी। जब हम चयन समिति में थे, तो मैंने और मेरे साथियों ने 60 खिलाड़ियों को चुना था: 20 खिलाड़ी मौजूदा भारतीय टीम में, 20 खिलाड़ी दूसरे स्तर पर और 30 खिलाड़ी तीसरे स्तर पर। हमारे पास ए, बी और सी टीमें थीं। क्या आप यकीन करेंगे– ऋषभ पंत, शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी हमारी तीसरी टीम, यानी सी टीम में थे। 'हमने खिलाड़ियों को एक स्तर से दूसरे स्तर पर इस तरह पहुंचाया कि 'ए' टीम की जरूरतों के हिसाब से हम 'बी' टीम के खिलाड़ियों को वहां शामिल करते थे, और फिर 'सी' टीम के खिलाड़ियों को 'बी' टीम में लाते थे।

तो, इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया थी। आज, सिलेक्शन कमिटी छोड़ने के पांच साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो पाता हूं कि जिन खिलाड़ियों को हमने पहचाना था–जो 'कैटेगरी सी' में थे–वे आज भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हैं। आपको और क्या चाहिए? मुझे लगता है कि हमने बिल्कुल सही लोगों को चुना था। भारत में महिला क्रिकेट के आगे बढ़ने के बारे में बात करते हुए, प्रसाद ने पूर्व बीसीसीआई सचिव और मौजूदा आईसीसी चेयरमैन जय शाह को इसका श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुरुष और महिला क्रिकेटरों की कमाई के बीच के अंतर को कम करने में जय शाह का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने महिला क्रिकेट टैलेंट पूल को शुरुआती दौर में विकसित करने में आंध्र क्रिकेट की भूमिका को भी याद किया। इसी दौरान लेफ्ट-आर्म स्पिनर एन. श्री चरणी की खोज हुई, जो आज विमेंस टी20 में टॉप रैंक वाली गेंदबाज हैं। 'मुझे लगता है कि भारत में महिला क्रिकेट के विकास के लिए कई लोग श्रेय के हकदार हैं। सबसे पहले, जब जय शाह भारतीय क्रिकेट की कमान संभाल रहे थे, तो उन्होंने पुरुष और महिला क्रिकेट के बीच आर्थिक अंतर को कम किया।

उनका मानना था कि महिला क्रिकेटरों को कहीं बेहतर भुगतान मिलना चाहिए। जैसे ही खिलाड़ियों की कमाई बढ़ने लगी, कई नई लड़कियां इस खेल से जुड़ने लगीं। उन्हें लगा कि वे इसके जरिए अपनी आजीविका चला सकती हैं। जब किसी खेल में अच्छा पैसा होता है, तो स्वाभाविक रूप से ज्यादा लोग उस तरफ आते हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि इसका श्रेय उन्हें जाना चाहिए। इसके अलावा, 2012-13 के दौरान, जब हम वहां थे, तब आंध्र क्रिकेट देश का पहला ऐसा एसोसिएशन था जिसने अपनी तरह की पहली महिला अकादमी शुरू की थी। 'क्या आप यकीन कर सकते हैं कि शुरुआती दो वर्षों तक 'नेशनल क्रिकेट एकेडमी' गुंटूर में थी? सभी नेशनल कैंप गुंटूर में ही आयोजित होते थे।

फिलिप्स-ब्लंडेल ने संभाली न्यूजीलैंड की पारी, पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम का स्कोर 246/5

क्राइस्टचर्च (एजेंसी) भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच हेगली ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 5 विकेट खोकर 246 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट में टॉस जीतकर पहले न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कीवी टीम की शुरुआत अच्छी रही और कप्तान टॉम लाथम और डेवोन कॉनवे ने मिलकर पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़े। कॉनवे 79 गेंदों का सामना करने के बाद 31 रन बनाकर आउट हुए।

दूसरे सेशन में आकाश दीप ने लाथम को अर्धशतक पूरा करने के बाद 59 रनों के स्कोर पर आउट किया। लाथम ने अपनी पारी में 128 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके लगाए। अगले ही ओवर में अंशुल कंबोज ने हेनरी निकोल्स को 16 रनों के स्कोर पर पवेलियन भेजा। आकाश दीप ने रचिन रवींद्र को बिना खाता खोले ऋषभ पंत के हाथों विकेट के पीछे कैच कराकर आउट किया। इसके बाद पांचवें विकेट के लिए टॉम ब्लंडेल और डेरिल मिचेल ने मिलकर 124 गेंदों में 74 रन जोड़े। मिचेल की 31 रनों की पारी का अंत वॉशिंगटन सुंदर ने किया। 184 के स्कोर पर न्यूजीलैंड को पांचवां झटका लगा। हालांकि, ब्लंडेल और ग्लेन फिलिप्स ने इसके बाद मोर्चा संभाला और न्यूजीलैंड का कोई और विकेट नहीं गिरने दिया।

पीसीबी ने किया महिला टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान, फातिमा-सादिया को ए कैटेगरी में मिली जगह

लाहौर (एजेंसी) पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने 2026/27 सीजन के लिए आठ महिला क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की है, जिसमें कप्तान फातिमा सना और सीनियर स्पिनर सादिया इकबाल को ए कैटेगरी में रखा गया है। 25 साल की फातिमा को बल्ले और गेंद दोनों से लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए इनाम मिला है। वह हाल ही में इंग्लैंड में 'द हंड्रेड' और ऑस्ट्रेलिया में 'विमेंस बिग बैश' में खेलने वाली पहली पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर बनीं। इस बीच, सादिया ने पाकिस्तान की टॉप परफॉर्मर में अपनी जगह बनाए रखी है। बाएं हाथ की स्पिनर पहले आईसीसी टी20 इंटरनेशनल बॉलिंग रैंकिंग में टॉप पर रह चुकी है।

मुनीबा अली सिद्दीकी, नशरा संधू और सिदरा अमीन को सभी फॉर्मेट में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन और योगदान के लिए कैटेगरी बी में रखा गया है। गुल फिरोजा और सदफ शमास की ओपनिंग जोड़ी को अनुभवी खिलाड़ी आयशा जफर के साथ कैटेगरी सी में शामिल किया गया है। उनका शामिल होना उनके हाल के घरेलू और इंटरनेशनल प्रदर्शन के साथ-साथ टीम की भविष्य की जरूरतों को दिखाता है। पीसीबी ने एक बयान में कहा, 'कॉन्ट्रैक्ट 30 जून, 2027 तक चलेंगे। खिलाड़ियों की हालिया फॉर्म और फिटनेस को देखते हुए कैटेगरी तय की गई हैं।

स्पेन ने कटाया डेविस कप के सेमीफाइनल का टिकट, ऑस्ट्रिया को 2-0 से दी शिकस्त

बोलोग्ना/इटली (एजेंसी) स्पेन ने गुरुवार को ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर डेविस कप फाइनल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम की जीत की नींव डेनियल मेरिडा ने रखी, जिन्होंने पहला मुकाबला जीतकर स्पेन को शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद राफेल जॉडार ने दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए पिछड़ने के बावजूद वापसी की और अपना मैच जीतकर स्पेन की टाई में जीत सुनिश्चित कर दी। इस जीत के साथ स्पेन ने कुल मिलाकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की और सेमीफाइनल का टिकट कटाया। एटीपी फाइनल्स में अपनी सफलता के बाद मौजूद रहे कार्लोस अल्काराज को कोर्ट पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि स्पेन का शनिवार को ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ आखिरी-चार का मुकाबला होना था।

मेरिडा ने शुरुआती सिंगल्स मुकाबले में जोएल श्वार्जलर पर 6-4, 6-4 की शांत जीत के साथ स्पेन की जीत की नींव रखी। फिर जॉडार ने यह पक्का किया कि निर्णायक डबल्स मैच की जरूरत न पड़े, और जुरिज रोडियोनोव के खिलाफ 2-6, 6-0, 6-1 से शानदार जीत हासिल की। पहला सेट हारने के बाद 20 साल के खिलाड़ी का जवाब खास तौर पर शानदार था, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए आखिरी 13 में से 12 गेम जीते। उनकी पहली सर्विस की काबिलियत अहम साबित हुई, जिसमें रोडियोनोव के साथ अपनी पहली एटीपी मीटिंग में जॉडार ने अपनी पहली डिलीवरी के बाद 94 प्रतिशत (63/67) पॉइंट जीते।

'यकीन करना मुश्किल है फिर बाहर कर दिया', सिराज को जगह न मिलने से नाखुश पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स



नई दिल्ली (एजेंसी)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को एक बार फिर प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी गई है। टीम मैनेजमेंट के इस फैसले पर भारत के पूर्व क्रिकेटर्स ने नाराजगी जताई है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ सिराज को एक बार फिर प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने से नाखुश दिखाई दिए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'यकीन करना मुश्किल है कि भारत के सबसे अच्छे तेज गेंदबाजों में से एक मोहम्मद सिराज को फिर से बाहर कर दिया गया है। सिराज को बुमराह के साथ भारत के विदेशी टेस्ट बॉलिंग अटैक में सबसे पहले चुना जाना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने खुद सिराज को वर्ल्ड-क्लास बॉलर कहा था और बताया था कि वह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं।'

वहीं, पूर्व तेज गेंदबाज मुनाफ पटेल ने लिखा, एक बार फिर मोहम्मद सिराज को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली।' मुनाफ ने अपने एक और ट्वीट में मौजूदा बॉलिंग अटैक पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा, चलो, कोई बात नहीं अगर आप मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपकी अगली बॉलिंग यूनिट कहां है, जो मैच जिताने में माहिर हो? क्रिकेट विशेषज्ञ और कमेंटेटर हर्षा भोगले ने अपने एक्स अकाउंट पर सिराज को लेकर लिखा, सिराज अब भारत के छठे रैंक वाले तेज गेंदबाज हैं।

पंकज आडवाणी की ऐतिहासिक जीत से भारत को मिली क्रूसिबल कप 2027 की मेजबानी

नई दिल्ली (एजेंसी)

पंकज आडवाणी रीडिंग में क्रूसिबल कप जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने दो दिन तक शानदार स्नूकर खेला, जिसका नतीजा फाइनल में टोनी ड्रैगो पर 6-0 की शानदार जीत के रूप में सामने आया। आडवाणी की जीत ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय होने से भी ज्यादा खास है, क्योंकि उन्होंने न केवल क्रूसिबल कप और 25,000 पाउंड की प्राइज मनी घर लेकर आए, बल्कि टूर्नामेंट का 2027 एडिशन भी भारत ले आए हैं।

क्रूसिबल कप लाइन-अप में रॉनी ओ'सुलिवन, डिफेंडिंग चैंपियन नील रॉबर्टसन, टोनी ड्रैगो, ड्रीम टिकट विनर बैरी पिंचेस, मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन वू यिजे, पहले चीनी स्नूकर 900 विनर झेंग यूझो, द जेंटलमैन जो पेरी, और आडवाणी शामिल थे। आडवाणी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया,



'मैदान कितना मुश्किल था, यह देखते हुए मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यह ट्रॉफी उठा पाऊंगा। खेल के कुछ महान खिलाड़ियों के साथ एक शानदार मैदान इस जीत को और भी खास बनाता है।' भारतीय खिलाड़ी ने डिफेंडिंग चैंपियन नील रॉबर्टसन को हराकर टूर्नामेंट की शुरुआत की थी। इस जीत के साथ ही आडवाणी ने दिखा दिया था कि वह खिताब को जीतने के प्रबल दावेदार हैं। सेमीफाइनल में आडवाणी का मुकाबला जो पेरी से हुआ, जिसमें भारतीय स्टार ने जीत हासिल करके और ड्रैगो के खिलाफ फाइनल में जगह बनाकर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा।

फाइनल शुरू होने से पहले, एक बड़ी घोषणा हुई कि विजेता न केवल क्रूसिबल कप ट्रॉफी और 25,000 पाउंड का पहला इनाम घर ले जाएगा, बल्कि हमने यह भी कन्फर्म किया कि क्रूसिबल कप 2027 इस साल के चैंपियन के गृहनगर में होगा। इसका मतलब था कि अगले साल के इवेंट की जगह भारत होगी, क्योंकि आडवाणी ने ट्रॉफी को अपने नाम किया है। फाइनल पूरी तरह एकतरफा रहा, जहां आडवाणी ने पूरे टूर्नामेंट में दिखाई गई अपनी बेहतरीन फॉर्म को बरकरार रखा। उन्होंने शुरुआत से ही मुकाबले पर नियंत्रण बना लिया और सेशन के बीच तक 4-0 की मजबूत बढ़त हासिल कर ड्रैगो पर लगातार दबाव बनाए रखा। स्नूअर 900 की रिपोर्ट के मुताबिक, झेंग यूबो और रॉनी ओ'सुलिवन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों पर शानदार जीत दर्ज करने के बाद फाइनल तक पहुंचने का सफर शायद माल्टा के स्टार खिलाड़ी ड्रैगो पर भारी पड़ गया, जिसका असर उनके प्रदर्शन में साफ दिखाई दिया। आडवाणी ने पूरे मुकाबले के दौरान अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी और कहीं भी धीमे पड़ने के संकेत नहीं दिए।

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी 'फ्लॉप', बारिश से प्रभावित मुकाबले को इंग्लैंड ने 7 विकेट से जीता, टी20 सीरीज में 2-1 से बढ़त

ब्रिस्बेन (एजेंसी)

इंग्लैंड ने बारिश से प्रभावित टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले को 'डकवर्थ लुईस नियम' के आधार पर 7 विकेट से अपने नाम किया। इसी के साथ मेहमान टीम ने पांच मुकाबलों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है। वनडे सीरीज 2-1 से जीतने के बाद इंग्लैंड ने टी20 सीरीज का पहला मैच गंवा दिया था। इसके बाद अगले मुकाबले को 8 विकेट से जीतकर सीरीज में बराबरी कर ली।

अब बढ़त हासिल करने के बाद इंग्लैंड की टीम 29 नवंबर और 2 दिसंबर को क्रमशः सिडनी और कैनबरा में सीरीज के शेष मुकाबले खेलेगा। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 16.5 ओवरों में महज 108 रन पर सिमट गई। यह इस फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया का अपने घरेलू मैदान पर टी20 क्रिकेट में न्यूनतम स्कोर है। मेजबान टीम को



11 के स्कोर पर कप्तान मिचेल मार्श (11) के रूप में बड़ा झटका लग गया था। इसके बाद जेक फ्रेजर-मैकगर्क ने सैम हार्पर के साथ दूसरे विकेट के लिए 23 गेंदों में 44 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 55 रन तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया को 5.1 ओवर में हार्पर के रूप में दूसरा झटका लगा, जो 14 गेंदों में 3 छक्कों और 1 चौके की मदद से 26 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ लग गया। मैकगर्क 11 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इनके अलावा, निखिल चौधरी ने 19 रन, जबकि मिचेल ओवन ने 17 रन बनाए।

विपक्षी खेमे से जेमी ओवरटन ने 4 ओवरों में सिर्फ 12 रन देकर 5 विकेट झटके, जबकि लियाम डॉसन ने 3 विकेट निकाले। इनके अलावा, सैम करन ने 1 विकेट झटका। इसके जवाब में, इंग्लैंड ने 8.5 ओवरों में जीत हासिल कर ली। सलामी जोड़ी के रूप में फिलिप साल्ट ने एन्यूरिन डोनाल्ड के साथ 14 गेंदों में 24 रन की साझेदारी की। साल्ट 7 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक ने डोनाल्ड के साथ मोर्चा संभाला। इंग्लैंड ने 3.5 ओवरों में 1 विकेट गंवाकर 45 रन बना लिए थे। इसी बीच बारिश ने दखल दिया।

खेल जब दोबारा शुरू हुआ, तब तक टीम को 97 गेंदों में 64 रन की दरकार थी। पांचवें ओवर में टीम को कप्तान हैरी ब्रूक (9) और डोनाल्ड (32) के रूप में दो झटके लगे और छठे ओवर में इंग्लैंड के खाते में सिर्फ 4 रन जुड़ सके। इंग्लैंड ने 6 ओवरों की समाप्ति तक 3 विकेट खोकर 53 रन बना लिए थे। इसके बाद फिर से बारिश ने व्यवधान पैदा किया। खेल फिर से शुरू हुआ, तो टीम को 17 ओवरों में 98 रन का लक्ष्य दिया गया। इसके बाद जॉर्डन कॉक्स और टॉम बैंटन ने मोर्चा संभाला।

एफआईएच यूथ हॉकी 5एस वर्ल्ड कप : पुरुष टीम की होगी ब्राजील से पहली भिड़ंत, बेटियां बांग्लादेश का करेंगी सामना

नई दिल्ली (एजेंसी)

भारत की युवा पुरुष और महिला टीम मिस्र में होने वाले पहले एफआईएच यूथ हॉकी 5एस वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेगी। पुरुष टीम अपने अभियान का आगाज ब्राजील के खिलाफ करेगी, जबकि महिला टीम पहले मुकाबले में बांग्लादेश से भिड़ेगी। दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला 9 दिसंबर को खेलेंगी। मिस्र की राजधानी काहिरा 7 से 12 दिसंबर तक पहले एफआईएच यूथ हॉकी 5एस वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगी। इस टूर्नामेंट में दुनिया भर की 24 टीमें भाग लेंगी, जिनमें 12 पुरुष और 12 महिला टीमें शामिल हैं।

यह हॉकी 5एस फॉर्मेट में युवा खिलाड़ियों के लिए आयोजित होने वाली पहली विश्व चैंपियनशिप होगी। पांच खिलाड़ियों वाले इस तेज रफ्तार फॉर्मेट की शुरुआत 2014 के यूथ ओलंपिक गेम्स में हुई थी। खास बात



यह भी है कि यह इस आयु वर्ग का पहला एफआईएच विश्व स्तरीय टूर्नामेंट होगा। भारत ने इस साल जुलाई में ओमान के मस्कट में हुई यूथ हॉकी 5एस एशियन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के बाद इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट के लिए क्वालीफिकेशन हासिल किया, जहां भारतीय युवा पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की की, तो महिला टीम ने सिल्वर मेडल जीता था। पुरुषों के ड्रॉ में भारत को बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड और चिली के साथ पूल बी में रखा गया है। युवा भारतीय टीम अपनी कॉन्टिनेंटल जीत की लय को आगे बढ़ाना चाहेगी और वैश्विक प्रतियोगिता के पहले एडिशन में अपनी मजबूत छाप छोड़ना चाहेगी।

ब्राजील के खिलाफ अपने पहले मैच के बाद भारतीय पुरुष टीम उसी दिन मिस्र से भिड़ेगी। वह 10 दिसंबर को कजाकिस्तान के खिलाफ अपने पूल स्टेज के मैचों का समापन करेगी। इस बीच, भारतीय युवा महिला टीम को मेजबान मिस्र, ब्राजील और कजाकिस्तान के साथ पूल ए में रखा गया है। मस्कट में सिल्वर मेडल जीतकर क्वालीफिकेशन हासिल करने के बाद भारतीय महिलाएं उस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर सम्मान के लिए मुकाबला करने के लिए उत्सुक होंगी। बांग्लादेश के खिलाफ शुरुआती मैच के बाद भारतीय महिलाएं 10 दिसंबर को स्विट्जरलैंड से भिड़ेंगी और फिर उसी दिन बाद में चिली के खिलाफ अपना पूल स्टेज खत्म करेंगी। पूल मैच 9 और 10 दिसंबर को होंगे और हर टीम तीन मैच खेलेगी।

हर पूल में सभी 12 टीमों को फिर रैंक किया जाएगा। तीन पूल विजेता और बेस्ट रनरअप सेमीफाइनल में जाएंगे, जो 11 दिसंबर को होंगे। फाइनल और ब्रॉन्ज मेडल मैच, साथ ही बाकी क्लासिफिकेशन गेम 12 दिसंबर को होंगे। हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल भोला नाथ सिंह ने दोनों टीमों पर भरोसा जताया और टूर्नामेंट से पहले शुभकामनाएं दीं।

आईपीएल 2027 : रोहित को फिर मिली 'मुंबई इंडियंस' की कमान

मुंबई (एजेंसी)

मुंबई इंडियंस (एमआई) ने आईपीएल 2027 के लिए रोहित शर्मा को फिर से टीम का कप्तान नियुक्त किया है। पांच बार की चैंपियन फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की। मुंबई इंडियंस ने अपने पांचों आईपीएल खिताब रोहित की कप्तानी में जीते हैं। रोहित भारतीय टीम के कप्तान के तौर पर भी सफल रहे हैं। उनकी अगुआई में भारत ने मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता था।

अब मुंबई इंडियंस को उम्मीद है कि रोहित एक बार फिर टीम को आईपीएल में सफलता दिलाएंगे। रोहित की वापसी ऐसे समय में हुई है



जब ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को इस महीने की शुरुआत में पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) में ट्रेड कर दिया गया। पंड्या ने 2024 से 2026 तक एमआई की कप्तानी की थी। रोहित 2011 में मुंबई इंडियंस से जुड़े थे। उनकी कप्तानी में टीम ने साल 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल का खिताब जीता। फ्रेंचाइजी की तरफ से जारी एक बयान में रोहित ने कहा, मुंबई इंडियंस मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रही है। इस टीम की कप्तानी करना मेरे लिए हमेशा गर्व की बात रही है। आगामी सीजन को लेकर नीता भाभी (नीता अंबानी) और आकाश (अंबानी) के साथ हुई बातचीत काफी उत्साहजनक रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं 20वें सीजन के लिए तैयार हूं।

आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए और अपनी 'पलटन' (फैंस) को जश्न मनाने के कई मौके देने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं। हमारा ध्यान अपने तरीके की क्रिकेट खेलने, एक साथ मिलकर मुकाबला करने और खेल का आनंद लेने पर होगा। फ्रेंचाइजी ने कहा कि वे टीम की कमान अपने सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक को वापस सौंप रहे हैं, जिन्होंने मुंबई इंडियंस (एमआई) में जीत की संस्कृति बनाई, युवा खिलाड़ियों का समर्थन किया और टीम के वफादार प्रशंसकों के साथ एक गहरा जुड़ाव कायम किया। मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है।

उन्होंने आईपीएल और अब बंद हो चुकी चैंपियंस लीग टी20 में कुल 163 मैचों में टीम की कप्तानी की। इनमें से 91 मैच जीते, 68 हारे और चार मुकाबले टाई रहे। उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस पांच बार आईपीएल फाइनल में पहुंची और हर बार चैंपियन बनी। हालांकि, कप्तान के तौर पर उनके आखिरी कुछ सीजन उतने सफल नहीं रहे।

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2027 : अर्जुन काधे और सिद्धांत बंथिया ने डबल्स मेन ड्रॉ में बनाई जगह

चेंगदू (एजेंसी)

भारतीय टेनिस खिलाड़ी अर्जुन काधे और सिद्धांत बंथिया की जोड़ी ने एशिया-पैसिफिक वाइल्डकार्ड प्ले-ऑफ जीतकर 'ऑस्ट्रेलियन ओपन 2027' में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। दूसरी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान के काइतो उएसुगी/ताकेरु युजुकी की जोड़ी को 7-6(4), 6-4 से हराया। शानदार प्रदर्शन के दम पर काधे और बंथिया ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2027 के डबल्स मुकाबलों के लिए वाइल्डकार्ड हासिल किया। इस जीत के साथ, बंथिया ने अपना



पहला ग्रैंड स्लैम खेलने का मौका पक्का कर लिया है, जबकि काधे ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना डेब्यू करेंगे। काधे जूनियर स्तर पर चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुके हैं।

वे 2025 में विंबलडन और यूएस ओपन का भी हिस्सा थे, जहां वे पहले ही राउंड में बाहर हो गए थे। उन्होंने नवंबर 2017 में वियतनाम के थू दाऊ मोट सिटी में अपना पहला आईटीएफ सिंगल्स खिताब जीता था। वहीं, बंथिया की एटीपी डबल्स रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 115 है, जो उन्होंने 21 सितंबर 2026 को हासिल की थी। वे वर्तमान में भारत के चौथे नंबर के डबल्स खिलाड़ी हैं। इस हफ्ते चीन में चेंगदू में आयोजित 'एओ 2027 एशिया-पैसिफिक वाइल्डकार्ड प्ले-ऑफ' के समापन पर दो सिंगल्स और दो डबल्स वाइल्डकार्ड तय किए जाने थे। गौरतलब है कि इस टूर्नामेंट में (मेंस और विमेंस, सिंगल्स और डबल्स मिलाकर) हिस्सा लेने वाले भारतीयों में केवल बंथिया, काधे और रामनाथन शामिल थे।

जहां कभी तबाही मचाई थी चट्टानों ने वहीं आज उभरी आस्था, जानें 31 दिव्य आकृतियों का रहस्य



2013 में केदारनाथ घाटी पर आई भीषण त्रासदी ने पूरे देश को हिला दिया था। उस दौरान पहाड़ टूटे, विशाल चट्टानें बहकर मंदिर के पास आकर रुक गईं और हजारों लोगों की जान बचाने में ढाल बनीं। आज वही चट्टानें एक नए आस्था केंद्र के रूप में लोगों का ध्यान खींच रही हैं।

चट्टानों पर दिखीं 31 रहस्यमयी आकृतियां

स्थानीय लोगों, पुजारियों और कई विशेषज्ञों के अनुसार, इन चट्टानों की सतह पर करीब 31 अलग-अलग आकृतियां उभरकर दिखाई दे रही हैं। इनमें भगवान शिव से मिलती-जुलती आकृतियां, नंदी के जैसे आकार, साधु-संतों की आकृतियों जैसी रेखाएं भक्तों के रूप में दिखने वाली उभरी रूप-रेखाएं दूर से ये आकृतियां साधारण सा पत्थर ही लगती हैं, लेकिन पास जाकर देखने पर इनके आकार बेहद स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस वजह से कई लोग इन्हें प्राकृतिक मूर्ति परिसर जैसा मानने लगे हैं।

क्या यह प्रकृति का चमत्कार या दिव्य संकेत?

अब तक वैज्ञानिक रूप से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ऐसी विशाल और गहरी आकृतियां चट्टानों पर कैसे बनीं। कुछ विशेषज्ञ इन्हें प्राकृतिक भू-आकृतिक संरचना बताते हैं, जबकि कई श्रद्धालु इसे शिव की उपस्थिति और दिव्य संकेत मान रहे हैं।

स्थानीय निवासियों का कहना है- '2013 की आपदा के बाद भी मंदिर सुरक्षित रहा... अब इन चट्टानों में शिव के रूप दिखना कोई साधारण बात नहीं है।'

तीर्थयात्रियों के लिए नया आकर्षण

इन चट्टानों को देखने के लिए अब केदारनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। लोग इन्हें आस्था का प्रतीक, चमत्कार का संकेत, प्रकृति की अद्भुत कला और शिव की कृपा मानकर प्रति दिन बड़ी संख्या में दर्शन करने आ रहे हैं।

रहस्य और श्रद्धा बढ़ाती अनोखी कहानी

चाहे ये आकृतियां संयोग हों या प्रकृति के अद्भुत खेल— केदारनाथ की ये चट्टानें अब एक नई आध्यात्मिक कहानी बन चुकी हैं। 2013 की त्रासदी के दौरान मंदिर को बचाने वाली ये चट्टानें आज श्रद्धालुओं की आस्था का नया केंद्र बनकर उभर रही हैं। यह घटना बताती है कि प्रकृति और आस्था जब मिलती हैं, तो इतिहास खुद-ब-खुद नई कहानी रच देता है।





बादलों का घर मेघालय : इन 5 जगहों की सैर आपको जीवन भर याद रहेगी, बनाएं ट्रिप का प्लान!

नॉर्थ-ईस्ट राज्य प्राकृति और सुंदर वादियों के लिए जाना जाता है। अगर आप मेघालय जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए है। मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है। यहां की सुंदरता दुनियाभर में फेमस है। मेघायलय में पानी भी शीशे की तरह चमकता है और घने जंगल की सुंदरता देखकर आप कहीं न कहीं खो जाएंगे। जो एक बार मेघालय घूमने जाएगा वो वही का होकर रह गया है। मेघालय में आपको पहाड़, झरने, नदियां, झील, हरे जंगल सबकुछ देखने को मिलेगा। आइए आपको बताते हैं आप किन जगहों पर जरुर घूमने जाएं।



डॉकी झील

डॉकी झील भारत-बांग्लादेश सीमा पर एक छोटा-सा शहर बसा है। डॉकी झील को उमंगोट नदी भी बोला जाता है, जो कि भारत से बांग्लादेश तक बहती है। इसका पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इधर नाव पर सफर करने से ऐसा फील होता है कि जैसे नाव हवा में है।

शिलॉन्ग

मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग घूमने जरुर जाएं। यह शहर बेहद ही खूबसूरत और हरियाली से घिरा हुआ है। मेघालय पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों में बसा हुआ है शिलॉन्ग। इसे मिनी स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। शिलॉन्ग में आप व्यू पॉइंट, लैत्कोर पीक, स्प्रेअद ईगल फॉल्स, लेडी ह्यदारी पार्क और एलिफेंट फॉल्स को जरुर देखें।

दावकी

अगर आप मेघालय जा रहे हैं, तो पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में स्थित दावकी छोटा सा टाउन है, यहां पर घूमने के लिए कई सारी जगहें हैं। इधर आपको सुंदर झरने देखने को मिलेंगे। दावकी में जाफलोंग जोरी पॉइंट, बुरहिल झरने, मावल्यान्नॉग, रिवाई जैसी खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर सकती हैं।

मौसिनराम

मेघालय के खासी हिल्स में मौसिनराम एक सुंदर बस्ती है, यह अपनी प्राकृतिक स्टैलेग्माइट शिवलिंग जैसी संरचनाओं के लिए जाना जाता है। यहां पर मावजिम्बुइन गुफा देखने को लायक मिलती है। इस गुफा में शिवलिंग भी रखी है, जो कि स्टैलेग्माइट के लिए जानी जाती है। यहां का वातावरण एकदम शांत और सुकून से भरा हुआ है। कलकल करता हुआ पानी की आवाज आपके मन को शांति प्रदान करेगा।

मावफलांग पवित्र वन

मेघालय में मावफलांग वन एक प्रचीन जंगल है, जो काफी शुद्ध व पवित्र माना जाता है। इस जंगल से एक भी पत्ती बाहर लेकर जाना माना है और इस जंगल में आपको रुद्राक्ष के पेड़ मिलेंगे, हर मुख वाली रुद्राक्ष पेड़ में लगी होती है।

मेघालय, जिसे 'बादलों का घर' कहा जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और क्रिस्टल-क्लियर नदियों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ शिलॉन्ग, डॉकी झील, दावकी, मौसिनराम और मावफलांग पवित्र वन जैसी मनोरम जगहें आपके मन को मोह लेंगी।

खूबसूरती और रोमांच का अनोखा संगम, हिमाचल का 'कौमिक' गांव, जहां चांदनी रातें बिखेरती हैं जादू

उत्तराखंड में ऐसी कई अद्भुत और शानदार जगहें मौजूद हैं, जहां पर घूमने के लिए हर मौसम में विश्व के हर कोने से पर्यटक पहुंचते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित कौमिक एक ऐसा गांव है, जिसकी खूबसूरती देखकर हर कोई अद्भुत ख्वाबों की दुनिया में चला जाएगा।

हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमाचल के हृदय में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसको उत्तराखंड की तरह ही 'देव भूमि' के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है, जो 'बर्फीले पहाड़ों के प्रांत' के नाम से फेमस है। उत्तराखंड में ऐसी कई अद्भुत और शानदार जगहें मौजूद हैं, जहां पर घूमने के लिए हर मौसम में विश्व के हर कोने से पर्यटक पहुंचते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित कौमिक एक ऐसा गांव है, जिसकी खूबसूरती देखकर हर कोई अद्भुत ख्वाबों की दुनिया में चला जाएगा। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कौमिक की खासियत और इसके आसपास कुछ अद्भुत जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं।

कौमिक गांव

कौमिक गांव को कई लोग कोमिक के नाम से भी जानते हैं। यह गांव खूबसूरत और मनमोहक गांव हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है।

कौमिक गांव हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से करीब 444 किमी दूर है। इसके साथ ही कौमिक गांव मनाली से 202, कुल्लू से 224 और रिकांग पिओ से करीब 228 किमी दूर है।

कौमिक गांव की खासियत

हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले की स्पीति में स्थित कौमिक गांव काफी ज्यादा खूबसूरत है। कौमिक गांव को भारत के अलावा दुनिया के सबसे गांव होने की ख्याति भी प्राप्ति होती है।

कौमिक गांव समुद्र तल से करीब 15 हजार फीट की ऊंचाई पर मौजूद कौमिक गांव ढके-ढके ऊंचे पहाड़, क्रिस्टल से अधिक साफ झील-झरनों का पानी और नीले आसमान के लिए जाना जाता है। कौमिक गांव की चांदनी रात पर्यटकों को सबसे अधिक आकर्षित करती है। यहां का शांत और शुद्ध वातावरण भी पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। इसलिए इस गांव को हिमाचल प्रदेश का हसीन जन्नत माना जाता है।



लुंडुप त्सेमो गोम्पा बौद्ध मठ

कौमिक गांव अपनी खूबसूरती के अलावा लुंडुप त्सेमो गोम्पा बौद्ध मठ के लिए भी आकर्षण का केंद्र माना जाता है। इस मठ के बारे में बताया जाता है कि इसका इतिहास करीब 500 साल से भी अधिक पुराना है।

पहाड़ी की चोटी पर मौजूद होने के कारण लुंडुप त्सेमो गोम्पा बौद्ध मठ को एक्सप्लोर करना बहुत लोगों का सपना होता है। मठ की ऊंचाई से कौमिक गांव के आसपास के लुभावने और हसीन दृश्यों को आंखों में कैद कर सकते हैं। आप चाहें तो यहां पर यादगार फोटोग्राफी भी कर सकते हैं।

एडवेंचर प्रमियों के लिए स्वर्ग

यह गांव सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि गोम्पा बौद्ध मठ और एडवेंचर प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग माना जाता है। यह गांव विश्व भर में सबसे ऊंचे ट्रैकिंग और हाईकिंग के लिए फेमस है।

सर्दियों के मौसम के अलावा आप यहां पर गर्मियों में भी आ सकते हैं। यहां पर हजारों लोग ट्रैकिंग, बाइक राइड और कैंपिंग के लिए भी आते हैं। आप यहां पर रॉक क्लाइंब का भी लुत्फ उठा सकते हैं।

ऐसे पहुंचे कौमिक गांव

बता दें कि इस गांव पहुंचना बेहद आसान है। इसके लिए आप दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से बस लेकर स्पीति वैली पहुंच सकते हैं। दिल्ली कश्मीरी गेट से स्पीति वैली के लिए बस चलती हैं। स्पीति वैली पहुंचने के बाद आप बाइक रेंट पर लेकर कौमिक गांव पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप शिमला से भी बस लेकर कौमिक गांव पहुंच सकते हैं।



ये कैसा झरना जो बहता है उल्टा! नीचे गिरने की बजाए ऊपर चढ़ता है पानी, देखकर हिल जाएगा दिमाग

भारत में प्रकृति के कई ऐसे चमत्कार हैं, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इन्हीं में से एक है महाराष्ट्र का नानेघाट वाटरफॉल, जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देता है। आमतौर पर झरने ऊपर से नीचे गिरते हैं, लेकिन यह झरना नीचे से ऊपर बहता दिखाई देता है। इस अनोखे नज़ारे को देखने के लिए हर साल भारी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं।

कहां स्थित है यह अनोखा झरना?

यह अनोखा झरना नानेघाट वाटरफॉल के नाम से मशहूर है और कोंकण समुद्र तट तथा जुन्नार नगर के बीच स्थित है। मुंबई से इसकी दूरी करीब 120 किमी और पुणे से लगभग 150 किमी है। नाना घाट और 'रिवर्स वाटरफॉल' के नाम से जाना जाने वाला यह स्थान अपने अनोखे प्राकृतिक दृश्य के कारण पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है।

क्यों बहता है यह झरना उल्टी दिशा में?

गुरुत्वाकर्षण के नियम के मुताबिक हर चीज ऊपर से नीचे की ओर आती है, लेकिन नानेघाट का यह झरना तेज हवाओं के कारण ठीक उल्टा व्यवहार करता है। यहां हवा इतनी तेज़ चलती है कि नीचे गिरता पानी हवा का दबाव पकड़कर ऊपर उड़ने लगता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इसी तेज हवा की दिशा और गति के कारण यह झरना उल्टी दिशा में बहता दिखाई देता है, जो इसे बेहद रहस्यमयी और अनोखा बनाता है।

इसे देखने पर क्या महसूस होता है?

जो भी इस झरने को पहली बार देखता है, वह दंग रह जाता है। दूर से ऐसा लगता है मानो पानी ऊंची पहाड़ी की तरफ ऊपर चढ़ रहा हो। यह अद्भुत नज़ारा लोगों को कुछ पल के लिए स्तब्ध कर देता है, क्योंकि प्रकृति का ऐसा उल्टा करिश्मा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता।

कैसे पहुंचे नानेघाट रिवर्स वाटरफॉल?

अगर आप नानेघाट रिवर्स वाटरफॉल देखने का प्लान बना रहे हैं, तो यहां पहुंचना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको कल्याण बस स्टैंड जाना होगा, जहां से जुन्?नार और नानेघाट के लिए नियमित बसें मिल जाती हैं। चाहें तो आप सड़क मार्ग से भी अपनी कार या टैक्सी से आराम से नानेघाट पहुंच सकते हैं। यहां तक पहुंचने का रास्ता सुंदर घाटों और हरियाली से भरा है, जो यात्रा को और भी खास बनाता है।

ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए स्वर्ग

नानेघाट ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह ट्रेल घाटघर के घने जंगल क्षेत्र का हिस्सा है और रोमांच से भरपूर प्राकृतिक रास्तों से होकर गुजरता है। कल्याण-अहमदनगर हाईवे से शुरू होने वाला यह ट्रेकिंग रूट साहसिक यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय है, क्योंकि यहां का शांत वातावरण, पहाड़ी दृश्य और ठंडी हवाएं पूरे सफर को यादगार बना देती हैं।

घूमने का सबसे अच्छा समय

नानेघाट रिवर्स वाटरफॉल को देखने का सबसे अच्छा समय मानसून का मौसम माना जाता है। जुलाई से सितंबर के बीच यहां की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। इस दौरान हवाएं बेहद तेज चलती हैं, जिसकी वजह से झरना सबसे मनमोहक तरीके से उल्टी दिशा में बहता दिखाई देता है। यही समय इस अनोखे प्राकृतिक चमत्कार को नज़दीक से देखने के लिए परफेक्ट माना जाता है।

